

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

9, जुलाई, 1976

खण्ड 2 अंक 5

अधिकृत विवरण

विशय सूची

भुक्रवार, 9 जुलाई, 1976

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(5) 1
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(5) 31
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(5) 33
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(5) 34
मेज पर रखे गए कागज पत्र	(5) 34
वि ोशाधिकार समिति के प्रारम्भिक प्रतिवेदन पे ा करना तथा	
अन्तिम प्रतिवेदन देने का समय बढ़ाना	(5) 35
लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन पे ा करना	(5) 36
दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं० 3) बिल, 1976	(5) 36
दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (सैकिण्ड अमेंडमेंट) बिल, 1976	(5) 50
दि पंजाब कोआप्रटिव (हरियाणा सैकिड अमेंटमेंट) बिल,	(5) 51

1976	
दि ईस्ट पंजाब मोलैसिज (कन्ट्रोल) हरियाणा अमैटमैट बिल, 1976	(5) 60
दि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूटस (हरियाणा अमैडमैट) बिल, 1976	(5) 62
दि पंजाब खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड (हरियाणा अमैडमैट) बिल, 1976	(5) 65
दि पंजाब भूदान यजना (हरियाणा अमैडमैट) बिल, 1976	(5) 66
दि डौरी प्रोहिबि ान (हरियाणा अमैडमैट) बिल, 1976	(5) 68
दि हरियाणा वैट्रनरी काउंसिल बिल, 1976	(5) 71

हरियाणा विधान सभा

भुक्रवार, 9 जुलाई, 1976

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चंडीगढ़ में 9.30 बजे प्रातः हुई। अध्यक्ष (चौधरी सरूप सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

Mr. Speaker: Question Hour.

Amount deposited for the street light on the Mathura Road

Ch. Ram Lal Wadha: Will the Chief Minister be state-

(a) The exact date for the amount deposited with the Haryana state Electricity Board by the Faridabadd Complex for the street light on the Mathura Road from one complex area to the other complex area; and

(b) the time by which the said work is likely to be completed?

State Minister for Irrigation & Power (Sardar Harmohinder singh):

(a) 17-5-74

(b) The work has been completed except 2 K.M. portion, which will be energized on receipt how material from

the Faridabad Complex administration, who hav committed to supply the same.

**Government and privately owned Agricultural
Tube wells in the State**

Ch. Dal Singh: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the total number of Government & privately owned agricultural tube wells in the state as on 31st March, 1976:

(b) the total number of Government and private agricultural tube wells installed in the state during the financial years 1974-75 & 1975-76 respectively:

(c) the total area irrigated by the government and privately owned agricultural tube wells during the financial year 1975-76 respectively;

(d) the amount of revenue realized by the Government from the agriculturists for the supply of water from Government tubewells during the year 1975-76?

State Minister for Irrigation & Power (Sardar Harmohinder singh Chatha):

(a) 1125 sate direct irrigation MITC tube wells, 1018 augmentation MITC tube wells and 204725 agricultural privately owned tube wells.

Tub wells installed during the
year

	1974-75	1975-76
State direct irrigation tub wells (MITC)	123	86
State augmentation tube wells (MITC)	97	95
Privately owned tube wells	22415	13651
(c) MITC MITC Augmentation direct irr. tube wells tub ewells	Privately owned tube wells	

Area irrigate	52188 hectares	Included in area under canal irrigation	719469 ;hectares
---------------	----------------	-----------------------------------------	------------------

(d) Rs. 40,74,961.58

चौधरी दल सिंह: स्पीकर साहब, उन्होंने फरमाया है 2 लाख 7 हजार ट्यूबवैल्ज है और एरिया पौने 8 लाख हैक्टेयर होता है, इसके हिसाब से एक ट्यूबवैल 4 हैक्टेयर एरिया इरिगेट करता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या एक ट्यूबवैल के पीछे यह 4 हैक्टेयर की इरिगे न कम नहीं है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: स्पीकर साहब, प्राइवेट ट्यूबवैल्ज के मुताल्लिक मैंने पहले भ अर्ज किया था कि उनका

एवरेज एरिया 2-3 हैक्टेयर से ऊपर ए गोयर्ड इरिगेट हो ही नहीं सकता।

Vasectomy and Tubectomy Operations

Ch. Shiv Ram Verma: Will the Minister for Industries be pleased to state-

(a) the number of Vasectomy and tubectomy operations performed, separately, under the Family planning in the state during period from 1st April, 1975 to 31st March, 1976;

(b) the age-limit prescribed for vasectomy operations ; and

(c) the steps taken by the government for providing incentives for family planning?

Industries Minister (Sh. Harpal Singh):

(a)	(i) Vasectomy operations	35012
	(ii) Tubectomy operations	22930
	total	57942

(b) No. exact age has been prescribed for vasectomy operation but according to the departmental instructions the males falling in the category of eligible couples (wife in the age group of 15 to 44 years) having two or more children and between the age of 25 to to 50 years are ordinarily operated

for vasectomy	
(c) with effect from 1 st Mya, 1976, a cash incentive to each acceptor of vasectom/Tubectomy is given as follows:-	
(i) Persons havein tow or less living children	Rs. 120 (including diet) and Transportation charges up to Rs. 5.
(ii) Persons having three living children	Rs. 70 (including diet) and Transportation charges upto Rs. 5
(iii) Persons with 4 or more living children	Rs. 40 (including diet) for vasectomy and Rs. 45 (including diet) for Tubectomy and Transportation charges up to Rs. 5 in both cases.

चौधरी िव राम वर्मा: स्पीकर साहब, वजीर साहब ने बताया है कि दो बच्चों के बाप को ज्यादा इनसैटिव मिलेगा, तीन वालों के पिता को उससे कम मिलेगा और चार वालों के पिता को उससे कम मिलेगा तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि जिसके बच्चे ज्यादा है उनको अगर ज्यादा इनसैटिव बढ़ाये तो उससे पापुले ान कंट्रोल में आने से ज्यादा फायदा नहीं होगा? वह लोग भी वैस्क्टमी आपे ान के लिय ज्यादा आयेगे?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब यह सैटर से पालिसी आती है अम उसके मुताबिक पैसा देते है ।

चौधरी विठ्ठल राम वर्मा: स्पीकर साहब, केन्द्रीय सरकार की पालिसी तो है ही लेकिन क्या आप अपने तजुबे के अनुरूप केन्द्रीय सरकार को सुझाव देगे कि इस तरह की पालिसी बनाने से हम पालुले इन कंट्रोल करने में ज्यादा सफल हो सकते है?

मुख्य मुत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): स्पीकर साहब, मेरे ख्याल में तो यह पालिसी ज्यादा अच्छी है । अगर 2-3 बच्चों के बाद आप्रे इन करवाना है तो मै समझता हूं वह ज्यादा बहादुरी करता है, अगर 5-7 बच्चे करके करवाये तो उसका क्या फायदा होगा?

चौधरी दल सिंह: क्या वजीर साहब के नोअिस में यह बात है कि कई ऐसे आदमियों के आप्रे इन किये जा रहे है जो औलाद पैदा करने के काबिल नही और कई लड़कों के आप्रे इन किए है जिनके औलाद नही थी?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, ऐसे कोई केस हमारे नोअिस में नही आये लेकिन अगर कोई आदमी जिसके औलाद न हो जो आप्रे इन कराना चाहता हो, हो सकता है उसका कर दिया हो लेकिन कोशिश यही की जाती है कि जिनके औलाद न हो वह न कराय । मै हाउस की इनफर्में इन के लिए बता देता हूं कि वैस्वटमी को बाद में ठीक भी किया जा सकता है । चौधरी दल

सिंह के नोटिस में अगर एक भी ऐसा केस है तो हमें बताये तो उसको ठीक कर देंगे।

श्री गिरी । चन्द्र जो ि: फ़ैमिली प्लानिंग से बर्थ-रेअ में कितने परसेटेज की कमी हुई है?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, हर साल बर्थ रेट कुछ न कुछ कम होती जा रही है और हमारे प्रांत हरियाणा में बर्थ रेअ ज्यादा नही है इस लिहाज से अक्वल नम्बर पर है।

चौधरी पीर चन्द: स्पीकर साहब, अगर किसी मंत्री ने 11वां बच्चा पैदा किया हो तो उसका आप्रें इन करवाने का इन्तजाम करवायेगे? (हंसी)

(कोई जवाब नही दिया गया)

चौधरी िावराम वर्मा: क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि जो परिवार नियोजन कार्यक्रम चल रहा है उसको अगर हम देखे तो पता लगेगा कि जब हरियाणा बना था उस समय जितनी आबादी थी आज उससे डेढ़ गुना हो गई है तो इसको फ़ैमिली प्लानिंग की सफलता कैसे कहा जा सकता है।

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, यह ठीक है आबादी जितनी तेजी से बढ़ी है उसको कंट्रोल करना जरूरी है इसलिए हमारी प्रधान मंत्री ने इसकी ओर ध्यान दिलाया है और हमारे यूथ लीडर श्री संजय गांधी ने भी यूथ्स को इस तरफ लगाया है

इसलिए मैं समझता हूँ सभी लोगों को चाहिए, चाहे वे कसी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, सब का फर्ज बनता है कि आबादी को कंट्रोल करने में मदद दें। हम चाहे जितनी भी प्रोडक्ट्स बढ़ा ले उस से हमारे जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक हम पापुलेट्स को कंट्रोल नहीं करेंगे। बहुत से मैम्बर साहिबान ने इस सम्बन्ध में हमारा सहयोग दिया है मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और मैं सबसे अपील करूंगा कि आप सब इस काम में हमारे साथ भागिल हों ताकि पापुलेट्स को कंट्रोल हो।

श्री धजा राम: क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि बढ़ती हुई आबादी को मदेनजर रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून लाने का विचार रखती कि जिनके तीन बच्चे हैं उनको लाजमी तौर पर आप्रेंटिस करवाना पड़े?

श्री बनारसी दास गुप्त: ऐसा है अध्यक्ष महोदय, हमने यह निश्चय किया था कि कानून के द्वारा बढ़ती हुई आबादी पर रोक लगाई जाए। उसके लिए हमने कानून का प्रारूप भी तैयार किया, हमारी मंत्री परिशद ने पास किया और ऐप्रूवल के लिए केन्द्रीय सरकार को भेजा। अभी तक वहां से ऐप्रूवल मिली नहीं है। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछले दिनों प्रधान मंत्री जी ने इस समस्या की गंभीरता को समझते हुए तमाम मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन दिल्ली में बुलाया था और उन सब उपायों पर बड़ी गंभीरता के साथ विचार किया गया था कि किस प्रकार बढ़ती हुई आबादी को रोका जाए। वहां विचार विमर्श

के बाद जा ककुछ हमने महसूस किया वह यह है कि केन्द्रीय सरकार की और प्रधान मंत्री जी की ऐसी नीति प्रतीत होती है कि वे इस समस्या को कानून के द्वारा रोकना नहीं चाहते। उनका इरादा है कि परसुए उन से, समझा बुझाकर या प्रचार से इस समस्या को हल किया जाए। अगर भारत सरकार ने हमें अनुमति दी तो हम हम अवश्य ही कानून पास करके इस कंट्रोल करेंगे।

श्री गिरी । चन्द्र जो जी: क्या मंत्री जी बताएंगे कि जो जिला या सब डिवीजन फैमिली प्लानिंग में अग्रणीय रहा हो उसको विकास कार्य के लिए प्राथमिकता दी जाने की कोई योजना है?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, इसके लिए हमने एक कम्युनिटी इंसेन्टिव स्कीम चालू की है। इसके अनुसार जो डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट, सैकिण्ड और थर्ड आता है उसको कुछ मदद की जानी है। डिवैल्पमेंट वर्कस के लिए फर्स्ट आने वाले को एक लाख रूपये, सैकिण्ड को 75 हजार रूपये और थर्ड को 50 हजार रूपये देने का प्रोविजन किया है।

श्री गिरि । चन्द्र जो जी: जो जिले पिछले साल अग्रणीय रहे है क्या उनको भी इंसेन्टिव दिया जाएगा?

श्री हरपाल सिंह: जी हा, उनको भी इसी लिहाज से दिया जाएगा।

चौधरी दल सिंह: स्पीकर साहब, आज प्रैक्टिकल काम करने का जमाना है। क्या मुख्य मंत्री जी यह आ वासन देगे कि

तमाम मिनिस्टर्ज को आप्रे इन करवा दिया जाएगा? वे यह भी बताएं कि अब तक कितने मिनिस्टर्ज ने आप्रे इन करवाया है? (विधन)

श्री बनारसी दास गुप्ता: चौधरी गोवर्धन दास को छोड़ कर सबका करवा दिया है.....(हंसी).....

विकास एवं स्थानीय प्रशासन राज्य मंत्री (चौधरी गोवर्धन दास चौहान): मैंने भी करवा लिया है।

राव बंसी सिंह: क्या मंत्री जी बताएंगे कि फैमिली प्लानिंग के अन्दर कौनसा जिला फर्स्ट आया है और कौनसा सैकिण्ड?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, पिछले साल सिरसा फर्स्ट आया है और महेन्द्रगढ़ भायद सैकिण्ड।

श्रीमती लेखवती जैन: जनाब, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया कि कानून बना नहीं सकते। मैं यह रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर कानून नहीं बना सकते तो कम से कम जितने हमारे ऑफिसिज हैं, म्यूनिसिपल कमिटीज हैं, कौन्टोनमेंट बोर्डज हैं, उनके जो अफसर साहबान हैं, वे अपने महकमे के आदमियों को समझा बुझा तो सकते हैं। प्रायः देखा गया है कि स्वीपर्ज के यहां ग्यारहा—ग्यारहा बारहा—बारहा बच्चे होते हैं। यदि उन्हें अफसर साहबान समझाएं तो हो सकता है कि कुछ फर्क पड़े। (विधन)
स्पीकर साहब, पिछले दिनों रेलवे मिनिस्टर साहब की एक स्टेटमेंट

अखबार में आई थी। उन्होंने रेलवे के अफसर साहबान को अपने कर्मचारियों को समझाने की अपील की थी। मैं समझती हूँ कि यदि हमारे यहां भी इस तरह की बात हो जाए तो काफी सुधार हो सकता है।

Mr. Speaker: Are you giving a suggestion or are you putting a supplementary?

चौधरी रिजक राम: स्पीकर साहब, फ़ैमिली प्लानिंग का जो प्रोग्राम चल रहा है इसमें काफी डिस्कानप हुई, सलाह म वरे हुए, प्रधान मंत्री की अध्यक्षमात में सैमिनार्ज भी हुए और मीटिंग्ज भी हुई। क्या मुख्य मंत्री जी यह फरमायेगे कि क्या वे यह पता लगा पास है कि क्या मुख्य करण है जिसकी वजी से आबादी तेजी से बढती है है? इसमें गरीबी का मिनिस्टर साहब ने फरमाया था कि इलैक्ट्रिके इन से फ़ैमिली प्लानिंग को बड़ी हैल्प मिलती है। हरियाणा में तो सैट परसैट रूरल इलैक्ट्रिके न हुई है। तो क्या वे बताएंगे कि इससे फ़ैमिली प्लानिंग में कुछ मदद मिली है या नहीं मिली है?

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, बिजली से फायदा तो जरूर पहुंचता है लेकिन रहने कार चूकि कुछ पैट्रन भी बदल गया है इसलिए कोई अधि लाभ भायद नहीं हुआ। ज्यादा आबादी बढने में कुछ अं गरीबी का भी है लेकिन अधिक कारण में और ही समझता हूँ। भारतवर्श की कुछ ऐसी परम्परा रही है कि यहां आ तीर्वाद दिया जाता है कि दूधो नहाओं पूतो फलो। ज्यादा

बच्चे जिसके हो उसको ज्यादा भाग्यवान समझा जाता है उस प्राचीनता का प्रभाव अभी तक चला आ रहा है।

चौधरी दल सिंह: बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए क्या सरकार विवाह के लिए लड़के की उमर 25 साल और लड़की की उमर 20 साल करने का विचार रखती है?

श्री बनारसी दास गुप्त: ऐसा सुझाव अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री सम्मेलन में आया था और उसके फलस्वरूप भादी के योग्य लड़के की उमर 21 साल और लड़की की उमर 18 साल कर रहे हैं। मैंने यह सुझाव रखा था कि लड़के की उमर 25 साल और लड़की की उमर 20 साल की जाए परन्तु हमारे कुछ मुख्य मंत्री जी खास तौर पर पहाड़ी इलाके को रिप्रैजेंट करते थे या आदिवासी इलाके को रिप्रैजेंट करते थे वे इससे सहमत तो थे लेकिन वे ऐसा समझते थे कि यह उनके प्रदेशों में प्रैक्टिकल नहीं होगा। इसलिए उमर कुछ बढ़ा बढ़ा कर 21 और 18 वर्ष ही की जा रही है।

श्री जगजीत सिंह टिक्का: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने अग्रणीय रहने वाले जिलों की पोजीशन तो बताई है लेकिन क्या वे ब्लॉक की पोजीशन भी बता सकेंगे?

श्री हरपाल सिंह: इसके लिए तो सैपरेट नोटिस चाहिए।

चौधरी रिजक राम: स्पीकर साहब, अभी मुख्य मंत्री जी ने फरमाया कि देश में और हरियाणा में विशेषकर ऐसे परम्परा

रही है कि लड़के का खास तौर पर पैदा होना अच्छा और जरूरी समझते रहे हैं। मैं उनसे आपके द्वारा अब यह पूछना चाहता हूँ कि दे । आजाद होने के बाद परसेन्टेज हो पापुले ान की बढ़ती है वह पहले ही निस्वत ज्यादा है या कम है?

श्री बनारसी दास गुप्त: आजादी के बाद तो वह बढ़ी है।

चौधरी रिजक राम: दे । आजाद होने के बाद परसेन्टेज पर थाउजैन्ड या पर हन्डर्ड बढ़ी है या कम हुई है?

श्री अध्यक्ष: आबादी पहले भी बढ़ती थी लेकिन अब कंपैरेटिवली पहले से ज्यादा बढ़ी है या कम बढ़ी है?

श्री बनारसी दास गुप्त: बर्थ रेट कम हुआ है लेकिन साथ साथ डैथ रेट भी बहुत कम हो गया है।

चौधरी ि तव राम वर्मा: स्पीकर साहब, फ़ैमिली प्लानिंग के लिए अर्षी तक इन्होंने जो साधन अपनाए हैं वह नसबन्दी और नलबन्दी है लेकिन दूसरे प्रचार जो इसमें सहायक हो सकते हैं जो हमें ाा से इस दे । में परम्परा रही है क्या उस प्रचार को भुर्ू करके इस काम में सहायोग प्राप्त नहीं किया जा सकता? ब्रह्मचारी रहने से मनुश्य की भाक्ति बढ़ती है, भारीरिक बल बढ़ता है और उसके विचार भी भुद्र होते हैं। अगर यह प्रचार किया जाए तो काफी असर हो सकता है। सरकार इस और क्या नहीं सोच रही है? एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ कि सरकार लोगों के

खान पान की तरफ भी ध्यान दे। यह सरकार तो खान पान की आदत को सुधारने की बजाय भाराब का प्रचार बढ़ाती जा रही है।
.....(विधन)

Mr. Speaker: Order please.

चौधरी ि तव राम वर्मा: स्पीकर साहब, इसका फैमिली प्लानिंग से ताल्लुक है जो भाराबर पीकर जाएगा, क्या वह फैमिली प्लानिंग के प्रचार पर ध्यान में रखेगा?

श्री अध्यक्ष: फैमिली प्लानिंग से तो तो बहुत सी चीजों का ताल्लुक है। आप कोई क्वै चन पुट करे।

चौधरी ि तव राम वर्मा: क्या सरकार इस वर विचार करेगी?

श्री बनारसी दास गुप्त: ऐसा है अध्यक्ष महोदय कि ये जो उपाय अपना रखे है वे तो हम इम्प्लीमेंट कराते हरे है दूसरे उपाय ये अपना ले। (हंसी)

चौधरी ि तव राम वर्मा: यह तो हो नही सकता यदि ये भाराब की दुकाने खोलते रहे। (विधन) क्या यह सरकार भाराब का प्रचार न करके ठीक खान पान और ब्रह्मचर्य आदि का प्रचार करेगी ताकि लोग बहुत जल्दी इसको अपनाएं?

श्री निहाल सिंह: क्या मुख्य मुंत्री जी के नोटिस में यह बात है कि कुछ व्यक्ति इस फैमिली प्लानिंग के खिलाफ है? हमारा

प्रचार तो यह है कि अगर बच्चा अभी नहीं, दो दो के बाद कभी नहीं। लेकिन इनकी पार्टी कहती है कि अगला बच्चा अभी अभी, आठ के बाद कभी नहीं। (हंसी)

चौधरी विठ्ठल राम वर्मा: स्पीकर साहब, मेरा सवाल यह है कि सरकार इस ओर क्या नहीं सोच रही है कि भाराब न पी जाये और खाने पीने के बारे में प्रचार किया जाये जिससे इस समस्या को हल करने में मदद मिल सकती है।

Mr. Speaker: order please. No repetition.

चौधरी विठ्ठल राम वर्मा: स्पीकर साहब, मेरे सवाल का तो जवाब ही नहीं आया।

चौधरी दल सिंह: स्पीकर साहब, एडहोक बेसिज पर टीचर लगाते हैं तो कहते हैं कि दो केस नस बन्दी के लाओं तब लगायेगे, इन्तकाल चढवाना हो तो कहते हैं कि नस बन्दी करओं, कर्जा लेना हो तो कहते हैं कि नस बन्दी करओं तो क्या सरकार ऐसी इन्स्ट्रक्शन जारी करेगी कि नसबन्दी जबरदस्ती न करके परसुए उन से की जाये?

श्री बनारसी दास गुप्त: अध्यक्ष महोदय ऐसा है कि जो भी उपाय हम अपनाते हैं, बढ़ती हुई आबादी को रोकने की लिए, उनकी ये विरोधी दल के भाई नुक्ताचीनी करते हैं इनहोंने अपनी भाषण में कभी नहीं कहा कि फैमिली प्लानिंग को अपनाना चाहिए। यह रिकार्ड निकलवा कर दे लो। जो भी काम हम करते

है, ये उसकी नुकताचीनी करते हैं सहयोग देने की बजाए इनकी नीयत यह है कि रूकावट डाली जाये। हम गौरव के साथ कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश में फैमिली प्लानिंग में, देश में प्रथम रहा है और जो भी तरीके अपनाते हैं वे परसुए इनके हैं, न हमने किसी के साथ ज्यादाती की है और न की जायेगी।

श्री रामधार गौड़: क्या सरकार ने कोई ऐसा उपाय किया है कि ज्यादात फैमिली सिस्टम रह सके क्योंकि ज्यादात फैमिली सिस्टम डिस्टर्ब हो गया हो तो मुझे पता नहीं, किसी और का तो डिस्टर्ब हुआ नहीं।

चौधरी हरस्वरूप बुरा: स्पीकर साहब, जो फैमिली प्लानिंग में आपसे इन करते हैं उसके लिए एक्सपर्ट डाक्टर लगाये जाये। एक्सपर्ट डाक्टरों द्वारा आपसे इन न होने के कारण हरियाणा के लोगों इस फैमिली प्लानिंग से दूर भाग रहे हैं वरना लोग आपसे इन कराने के लिए तैयार हैं। मैं मिनिस्टर महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या इस प्रोबलम की तरफ ध्यान दिया जायेगा?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, यह बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि आपसे इनके लिए एक्सपर्ट नहीं भेजे जाते हैं। जो भी डाक्टर इस काम को जानते हैं, उनकी डियूटी लगायी जाती है।

चौधरी विठ्ठल वरमा: जैसाकि मंत्री महोदय ने अपने जवाब में लिखा कि 25 से 50 की उम्र तक लोगों का आपसे इन

किया जाता है तो मैं मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूँ कि क्या कोई आयु निश्चित नहीं है क्योंकि आयु निश्चित न होने से गलतियाँ होने की सम्भावना है, क्या सरकार आयु निश्चित करने पर विचार करेगी?

श्री हरपाल सिंह: कल को वर्मा साहब आपसे आकराने के लिए आयेगे तब उनकी आयु निश्चित कराने का सवाल पैदा होगा। इसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि पचास साल के बाद अगर कोई व्यक्ति आपसे आन करवाता है तो उसको हम इन्सैटिव मनी नहीं देते। कई बार ऐसा होता है कि कोई पचास की आयु में दुबारा भाँदी करवा ले तो नयी भाँदी होने के कारण उसकी बीबी की री-प्रोड्युक्शन ऐज होती है तो इन हालात के अन्दर आपसे आन करवा ठीक समझते हैं।

चौधरी फूल चन्द (रोहट): स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा चीफ मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करना चाहता हूँ.....

श्री अध्यक्ष: प्रार्थना नहीं सप्लीमैटरी करो।

चौधरी फूल चन्द (रोहट): स्पीकर साहब, मैं फैमिली प्लानिंग का बड़ा समर्थक हूँ मैं चाहता हूँ कि फैमिली प्लानिंग कामयाब हो। फैमिली प्लानिंग को कामयाब करने के लिए कोई जबरदस्ती करनी पड़े तो भी मुझ कोई एतराज नहीं। मैं इस बारे में एक बात कहता हूँ कि आपसे आन की मेज पर ले जाने से पहले यह चैक किया जाना चाहिए कि वह आपसे आन के काबिल भी है

या नहीं, खून की मिकदार है या नहीं। कुछ केसिज में जो खराबी आती उसकी वजह यही है कि उनको चैक नहीं किया जाता। दूसरे जो यह फैमिली प्लानिंग का अभियान चला उसमें कुछ स्कूल मास्टर्ज और मास्टरानियां अभी हाल तक भागह हुए हैं जबकि हमारा टारगेट भी पूरा हो चुका है तो क्या सरकार उन मास्टर्ज और मास्टरानियों को वापिस घर लाने का कश्ट करेगी?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, चौधरी फूल चन्द जी ने गलत कहा है कि टीचर्ज लौटे नहीं हैं और अभी तक भागे हुए हैं। दूसरी बात स्पीकर साहब यह है कि जो स्ट्रलाइजे इन करवा लेते हैं उनको सैटीस्फाइड कस्टमर्ज कहते हैं। डिपार्टमेंट उनको यूज करता है। वे सैटस्फाइड आदमी वहां कैम्पो में जाते हैं और लोगों में प्रचार करते हैं, उनको समझाते हैं कि हमने आपसे इन करवाया था, वह ठीक हुआ है। चौधरी फूल चन्द जी भी हमारे सैटीस्फाइड कस्टमर बन जायें तो हम उनके धन्यवादी होंगे।

चौधरी बृज लाल: स्पीकर साहब, यह जो आपसे इन होते हैं, उनमें 70-70 साल के बूढों के भी आपसे इन हुए हैं, यहां तक उन लोगों के भी हुए जिनकी औरते नहीं है। तो क्या मंत्री महोदय ऐसे केसिज में आपसे इन कने पर पाबन्दी लगायेगे?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, हमारे डायरैक्टर सौन्धी साहब बता रहे थे कि एक कैम्प में कोई 60-70 साल का बूढा आपसे इन कराने पर पाबन्दी लगायेगे?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, हमारे डायरेक्टर सौन्धी साहब बात रहे थे कि एक कैम्प में कोई 60-70 साल का बूढ़ा आपरे इन करवाने के लिए आ गया। सौन्धी साहब ने कहा कि तेरी उम्र भी ज्यादा है और तेरी औरत भी नहीं इसलिए आपरे इन कराने की क्या आवश्यकता है। कुछ नौजवान जो वहां खड़े हुए थे वे हंसने लगे। तो उस बूढ़े ने ज्वाब दिया कि मेरी बीबी नहीं है तो इन नौजवानों की तो है। (हंसी)

चौधरी रिजक राम: अभी मुख्य मंत्री महोदय ने फरमाया है कि फैमिली प्लानिंग का अभियान चलाने के बावजूद भी जितना बर्थ रेट रूकना चाहिए उतना रूका नहीं है मैं एक बात का हवाला देते हुए मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कुछ अर्सा हुआ एक स्त्रीको बच्चा पैदा हुआ लेकिन उसका खाविन्द बहुत मुददत से बाहर रहता था। पडोस की औरतों ने पूछा कि खाविन्द तो बाहर रहता है तुम्हे बच्चा कैसे पैदा हो गया। सास ने कहा कि खतो खियाताबत होती थी उससे बच्चा पैदा हो गया। औरतों ने कहा कि चिट्ठी से कैसे पैदा हो सकता है? उनकी सास ने कहा कि मुझ जब यह बच्चा पैदा हुआ तो चिट्ठी भी नहीं आयी थी तो क्या मुख्य मंत्री जी को इज्जल्म है कि जिस प्रकार से जनता बच्चा पैदा करने के नये नये डिवाइसिज सोच रही है, क्या इसी प्रकार सरकार भी बच्चे न पैदा होने के लिये नये डिवाइसिज पर विचार कर रही है?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, मेरी प्रार्थना है कि मैम्बारान को मर्यादा के अन्दर ही प्र न पूछने चाहिए।

चौधरी फूल चन्द (रोहट): स्पीकर साहब, अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम में तेजी लाने के लिए पटवारी लोगों को परसुएड करते हैं और बाकायदा तसल्ली करवा करवा उनका आपरे न किया जाता है। अभी पिछले दिनों एक आदमी कोक पटवारी परसुएड करके आपरे न के लिए लाए और जब कपड़े उतार कर उसको कमरे में ले जाया गया तो डाक्टर औजार निकाल कर लाया। वह आदमी औजार देखकर अपने कपड़े उठाकर भाग गया। उसके पीछे पटवारी भागा और उसके पीछे डाक्टर। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या औजार के बगैर फैमिली प्लानिंग का कोई और ऐसा तरीका नहीं है?

श्री बनारसी दास गुप्त: ऐसे भी है। औजारों के बगैर भी फैमिली प्लानिंग की जासकती है।

श्री अध्यक्ष: अगर कोई ऐसा तरीका हो तो रोहट साहब का आपरे न बगैर औजारों के कर दो।

Case of Embezzlement in the Cooperative Societies

* **Rao Dalip Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the total number of cases of embezzlement in the cooperative societies registered in the state during the financial years 1972-73, 1973-74, 1974-75, 1975-76 and 1976-77 to date;

(b) the total amount involved in the case of embezzlements referred to in part (a) above; and

(c) whether any amount has been recovered so far?

Mr. Speaker: Extension has been asked for in respect of this question which has been granted. The communication received from the Chief Minister is as follows:-

BANARSI DASS GUPTA
76/3453

Cii-

Chief Minister, Haryana,

Chandigarh.

Chandigarh, dated the 6th July, 1976

Subject: Starred Assembly question No. 1671 asked by Rao Dalip Singh, M.L.A. regarding cases of embezzlement in the cooperative societies.

My Dear Ch. Sahib

I write to inform you that starred Assembly Question No. 1671 asked by Rao Dalip Singh, M.L.A., was received in the Secretariat (in Cooperation Department) on the 24th June, 1976. This Question has been fixed for answer on

9th July, 1976. As some information pertaining to this question is yet to be collected, I shall therefore, feel grateful if this question is fixed for answer on any date after the 24th July, 1976.

with regards,

Yours Sincerely

Sd/-

(BANARSI DASS GUPTA)

Ch. Sarup Singh

Speaker,

Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh.

Buses allocated to Rohtak Depot and its Sub Depots

***1676 Sh. Partab Singh Tiagi:** Will the Minister for transport be pleased to state-

(a) the total number of buses allocated to Rohtak Depot and its sub depots i.e. Jhajjar, Gohana and Sonapat during the period from April, 1975 to March, 1976 alongwith the models

(b) the number of buses out of those referred to in part (a) above which are not in working condition in the above said sub-depots; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to make a full fledged depot at Sonapat?

शिक्षा एवं परिवहन राज्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी):

(क), (ख) तथा (ग) अपेक्षित सूचना सदन की मेज पर रखी जाती है।

रोहतक डिपो तथा इसके अधीन उप डिपुओंको ऐलोकेट की गई बसों की सूचना

(क) अप्रैल, 1975 से मार्च, 1976 की अवधि में रोहतक डिपु को 30 नई गाड़ियां दी गई थी। प्रत्येक सब डिपों को दी गई गाड़ियों की संख्या नीचे दी गई है:—

सब डिपु का नामु	नई गाड़िया दी गई
रोहतक	21
झज्जर	4
गोहाना	4
सोनीपत	1

सब डिपो में माडल के अनुसार विवरण निम्न प्रकार से

है:—

माडल	रोहतक	गोहाना	झज्जर	सोनीपत
1968	24	2	2	
1969	20	3	3	5
1970	22	5	6	2
1971	12	11	6	3
1972	7	2	8	9
1973	17	5	2	2
1974	4	4	4	
1975	30	2	2	1
कुल	136	34	33	22

(ख) भाग (क) में दी गई सब डिपों की सब गाड़िया चालू हालत में है।

(ग) इस समय सोनीपत में मुख्य डिपों खोलने का प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।

श्री प्रताप सिंह त्यागी: स्पीकर साहब, रोहतक डिपों को 30 बसे अलाट की गईं जिनमें से सोनीपत सब डिपों को सिर्फ 1 बस दी गई है और 1969 में बीस बसों में से सिर्फ 2 बसे दी गई है। सोनीपत में काफी रूका रहता है और जो भी वहां बसे है वह भी काफी खराब हालत में हैं क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि सोनीपत डिपों को कम बसें देने का क्या कारण है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, सब डिपों पर बसे जरूरत के अनुसार दी जाती है और सोनीपत ऐसी जगह है जो दिल्ली और चण्डीगढ़ के रास्ते में आती है और इसलिए आने जाने वाली बसे उधार से बहुत संख्या में गुजरती है।

चौधरी फूल सिंह कटारिया: स्पीकर साहब, झज्जर सब डिपों में बहुत थोड़ी बसें हैं और वह रास्ते में भी नहीं पड़ता जैसे कि सोनीपत पड़ता है। क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि झज्जर सब डिपों पर और ज्यादा बसें दी जाएंगी?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, झज्जर सब डिपों में तो सोनीपत सब डिपों से भी ज्यादा बसें हैं। जरूरत के मुताबिक बसें दी जाती हैं। झज्जर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आनरेबल मैम्बर किसी और जगह कानाम बताएं जहां बसों की जरूरत है तो उसको दिखवा लिया जायेगा।

श्री गौरी भांकर: स्पीकर साहब, ऐसा देखा गया है कि बस के अन्दर दूसरा यानी फालतू टायर नहीं होता और अगर बस

रास्तों में टायर की वजह से खराब हो जाए तो वही खड़ी रह जाती है। क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि बस के अन्दर फालतू टायर सप्लाई किया जाएगा?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: ऐसी कोई बात नहीं है। कोर्पोरेशन यही होती है कि स्टेपनी हरेक बस में हो।

चौधरी मनफूल सिंह: क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि झज्जर सब डिपों में कितनी बसें हैं और उनको मेक क्या है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, झज्जर सब डिपों में 33बसे हैं। इनमें से 1968 की 2, 1969 की 3, 1970 की 6, 1971 की 8, 1973 की 2, 1974 की 4 और 1975 की 2 बसे हैं।

चौधरी फूल चन्द (रोहट): स्पीकर साहब, रोहतक के सब डिपों सोनीपत में जो बसिज हैं वे सारी बसिज नकारा हैं। तकरीबन हर रोज तीन चार बसिज रास्ते में खड़ी रहती हरूँ ओर जो चलती भी वे बहुत ज्यादा आवाज करती हैं.....

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज, यह सप्लीमैटरी नहीं है।

चौधरी फूल चन्द (रोहट): स्पीकर साहब, मेरे कहने का मतलब यह है कि जो बसिज का ऐलोकेशन है वह ठीक नहीं है। स्टाफ से जब हम पूछते हैं कि भई आपकी बसिज क्यों खराब रहती है तो वे कहते हैं कि ये पुरानी बसिज हैं यह जहै पूरी

जानकारी के आधार पर कह रहा हूँ क्या मंत्री महोदया इसका इन्तजाम करने की कृपार करेंगी?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, ऐसी बात नहीं है कि सोनीपत सब डिपों में खराब बसें दी जाती ह। जब बसिज इतना सफर करती है तो कही ब्रेक डाउन भी हो सकता है।

श्री अमर सिंह: क्या मंत्री महोदया बतान की कृपा करेगी कि भिवानी डिपों में कितनी बसिज है और वहां कितनी बसों की डिमान्ड थी?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, टोटल बसें तो बताई जा सकती है। वैसे इस सप्लीमैटरी का क्वे चन से कोई सम्बन्ध नहीं है इसके लिए अलग से नोटिस चाहिए।

चौधरी फूल सिंह कटारिया: क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि झज्जर सब डिपों में जो 33 गाड़िया है उनमें से 12 गाड़ियों को ब्रेक डाउन हुआ रहता है इसका क्या कारण है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, ऐसी बात नहीं है कि वे गाड़ियां चलती ही नहीं है। थोड़ी बहुत मरम्मत के लिए गाड़ी वर्क गप आती रहती है ओर रिपेयर होने के बाद रोड पर आ जाती है।

चौधरी मेहर चन्द्र: स्पीकर साहब पंडित चिरंजी लाल की कृपार से हमारे यहा एक सड़क बन गई है और वह सड़क है भट्टू से लेकर चूडी बागड़िया। यह ऐसी सड़क है कि भट्टू से चूडी बागड़ियां आने पर हिसार डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि उस रोड़ पर कब तक बस चलाने की कृपा की जाएगी?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: वैसे तो जहां सड़क पूरी हो जाती है और जनता की मांग होती है और यह देखा जाता है कि बस चलाना जरूरी है तो वहां बस चलाने की इन्तजाम किया जाएगा?

Mr. Speaker: Order please. This is not a su;;oementary. This is a suggestion. I will not allow it.

चौधरी पीर चन्द: क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेगी कि 1975-76 में हिसार डिपों को कितनी बसें भेजी गईं?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: इसके लिए अलग से नोअिस चाहिए।

चौधरी दल सिंह: स्पीकर साहब, मैं कल दिल्ली गया था, मैं इस पर एक सवाल भी करूंगा। उस बा का रस्ते में एक स्कू ढीला हो गया और इस वजह से चार-पांच लीअर डिजल बाहर निकल गया। वह स्कू मुि कल से दस आने का आता है होगा और उसकी वजह से दस रूपएण का डिजल खराब हो गया।

उस बस में कोई टूल नहीं था जिससे कि ड्राइवर उसको ठीक करता। उस बस का नम्बर एच. आर. ए. 9859 है। क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि इसका क्या कारण है कि बस के अन्दर एक टूल भी नहीं होता और जाने से पहले उसकी चैकिंग नहीं की जाती?

परिवहन मंत्री (श्री के. एल. पोसवाल): स्पीकर साहब, जब से हमने ट्रांसपोर्ट को ने नेलाइजे न किया है हमने ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें जुटाई हैं जी. टी. रोड पर एक रिपेयर के लिए बड़ी वैगन रहती है, कोई भी बस खराब हो जाए, किसी भी डिपों की बस खराब हो जाए उसको ठीक करते हैं। हर बस के अन्दर एक टूल बाक्स होता है जिससे छोटी मरम्मत आपने आप भी की जा सकती है। अगर कोई गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है तो नियरैस्ट जगह पर इंफरमे न देते हैं और थोड़ी देर में ही खराब गाड़ी को रोड पर ले आते हैं।

श्री प्रताप सिंह त्यागी: स्पीकर साहब, मैंने सोनीपत जिला के मुताल्लिक दो तीन पद्य तैयार किये हैं, आपकी इजाजत से वह मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ।

(क) मुफ्त हुए बदनाम सोनीपत जिला बनाके

इसमें एक सब डिपों सोनीपत है

क्या बताऊ रूट 24 है, बसे है 20

उनकी खट खरूट की मुसीबत है

थक गए पलटू और मुखराम

बसों में धकके लगाके,

मुफ्त हुए बदनाम सोनीपत जिला बनाके ।

(ख) सात-आठ साल एक पुरानी है,

नो की छः साल जिदगानी है ।

दो है चौ साला.....(हंसी)

श्री प्रताप सिंह त्यागी: स्पीकर साहब, मैने तो सरकार आपसे पहले ही इस बारे में इजाजत ले ली थी ।

श्री अमर सिंह: स्पीकर साहब, अक्सर बसे रोडज के ऊपर खराब हालत में खड़ी हो जाती है और जो दूसरे डिपोज की बसें होती है वह रास्ते में खड़ी नहीं होती जिसके कारण सवारियों को बड़ी तकलीफा होती है । क्या ऐसी बात सरकार के नोटिस में है? क्या सरकार कोई कदम उठाने का विचार रखती है कि जब कभी कोई बस रास्ते में खराब हो जाए तो दूसरे डिपोज वाली बसें उनको अपना पूरा सहयोग दें?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, ऐसी कोई बात हमारे नोटिस में नहीं आई कि दूसरे डिपोज की बसें रास्ते में न रुकती हो और सवारियों को न ले जाती हो ।

श्री राम धारी गौड़: स्पीकर साहब, गोहाना का बस डिपों अभी फूल फलेजड नहीं है और वहां से सरकार को आमदनी भी बहुत ज्यादा है कया मिनिस्टर साहिबा बताएंगी कि कब तक वहां पर फूल फलेजड बस डिपों बना दिया जाएगा?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, ऐसी कोई परपोजल आगी तक सरकार के विचारधनी नहीं है और न ही सरकार आगी तक कोई ऐसी जरूरत ही महसूस कर रही है।

चौधरी फूल चन्द (मुलाना): स्पीकर साहब, कुछ ब्रेकडाउन हुई बसे सड़कों से तो ठीक आ जाती है लेकिन जब वे बस अड्डो में एन्टर करती है तो वहां पर बड़े-2 खड्डे है जिनके कारण वे खराब हो जाती है, मिसाल के तौर पर अम्बाला भाहर का बस अड्डा जो है वहां पर बहुत बड़े-2 खड्डे है। क्या सरकार इस तरफ भी ध्यान देने की कृपा करेगी अगर देगी तो कब?

श्री के. एल. पोसवाल: स्पीकर साहब, जो बात मैम्बर साहब ने अम्बाला भाहर के अड्डे के बारे में कही है, वह बिल्कुल दुरस्त है और हम इसकी जल्दी ही मुरम्मत करवाने जा रहे है।

Amount spent for the purchase of spare parts

***1608 Ch. Ram Lal Wadhwa:** will the Minister for Transport be pleased to state-

(a) the deposit wise total amount spent on the purchase of spare parts, Tyres and Tubes separately by the Haryana Roadways during the financial years from 1972-73 to 1975-76 separately;

(b) the value of the spare parts and Tyres and Tubes which were lying in the stock of each depot of the Haryana Roadways as on 31st March 1972, and

(c) the Value of the spare parts and Tyres and Tubes used during the period as referred to in part (a) above together with the cost of the spare parts, Tyres and Tubes lying in the stores/Stock to-date, deposit-wise, separately?

शिक्षा एवं परिवहन मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी): (क)
(ख) तथा (ग) कथन 1 तथा 2 सदन की मेज पर रखे जाते हैं।

(क) वित्तीय वर्ष 1972-73 से लेकर 1975-76 तक प्रत्येक डिपों द्वारा स्पेयर पार्टस, टायरज तथा टयूबज की खरीद का पृथक-2 रूप में कुल खर्च की गई धन राशि का विवरण

	1972-73		1973-74	
	स्पेयर पार्टस	टायर और टयूबज	स्पेयर पार्टस	टायर और टयूबज
अम्बाला	2159948.00	1551385.00	3119607.00	1258316.00
गुडगांव	3146944.00	1809562.00	4932520.00	23.15742.00
चण्डीगढ़	1188320.00	967931.00	1216498.00	9.80572.00
रोहतक	2585494.11	2362.075.83	3365601.56	2444337.67
करनाल	1903252.69	1461396.57	2526774.57	1270134.38
हिसार	2792554.00	1854250.00	3236555.00	1655084.00

रिवाड़ी	462399.00	138293.00	1666032.00	10.105969.00
जींद	850799.52	83957.00	1643451.00	676114.00
भिवानी			781663.00	325228.00
कैथल				
	1974-75		1975-76	
	स्पेयर पार्टस	टायर तथा टयूबज	स्पेयर पार्टस	टायर तथा टयूबज
अम्बाला	4146467.00	2001076.00	4573609.00	1997091.00
गुडगांवा	3838872.00	2541963.00	4588576.00	3131348.00
चण्डीगढ	2380407.00	1835527.00	2085420.00	2123814.00

रोहतक	4275738.32	3766337.00	5233300.66	2853097.61
करनाल	3809226.43	2014955.19	3341920.41	1264788.83
हिसार	3556385.00	2928998.00	3869567.00	2732547.00
रिवाडी	1865131.00	2040905.00	2255459.00	2263660.00
जींद	2081694.00	1309827.00	2070623.94	1385951.08
भिवानी	2666046.00	1383420.00	2207132.00	1626219.00
कैथल	2493099.45	798934.15	2693403.87	1414.885.37
(ख) 31.03.1972 को हरियाणा रोडवेज के प्रत्येक डिपो के स्टॉक में पड़े स्पेयर पार्ट्स, टायरज तथा ट्यूबज की कुल कीमत				
	स्पेयर पार्ट्स		टायरज एवं ट्यूबज	

अम्बाला	1711414.00	87814.00
गुडगांवा	2124462.00	1495566.00
चण्डीगढ	1077578.00	171087.00
रोहतक	1965064.00	37349.00
करनाल	1601847.23	44017.38
हिसार	1672365.00	2467.00
रिवाडी	इस डिपों की स्थापना 1.12.1972 में हुई	
जींद	इस डिपों की स्थापना 1.1.1973 में हुई	
भिवानी	इस डिपों की स्थापना 1.11.1973 से हुई	
कैथल	इस डिपों की स्थापना 20.08.1974 से हुई	

(ग) उपरोक्त भाग (क) में वर्णित समय के मध्य में प्रत्येक डिपु में प्रयोग में लाए गए स्पेयर पार्ट्स, टायरज तथा टयूबज की कीमत तथा तक स्टोर/स्टाक में पड़े स्पेयर पार्ट्स, टायरज तथा टायूबज की कुल कीमत

(1) भाग (क) में वर्णित समय के मध्य प्रयोग में लाए गए स्पेयर पार्ट्स, टायरज तथा टयूबज की कीमत

	1972-73			1973-74		
	स्पेयर	टायर	और	स्पेयर	टायर	और

	पार्टस	टयूबज	पार्टस	टयूबज
अम्बाला	2293357.00	1538398.00	3202306.00	1300181.00
गुडगांव	2415659.00	1558518.00	2373322.00	1546315.00
चण्डीगढ	1067648.00	790687.00	1218923.00	870647.00
रोहतक	2640707.68	2201811.49	3256162.11	2548834.21
करनाल	213706460	1251142.19	2098043.93	1362521.10
हिसार	1672365.00	21467.00	1933515.00	218894.00
रिवाड़ी	382561.00	183030.00	1075695.00	861599.00
जींद	268602.52	59838.00	1313855.00	629756.00
भिवानी			668223.00	329891.00

कैथल				
------	--	--	--	--

	1972-73		1973-74	
	स्पेयर पार्टस	टायर टयूबज और	स्पेयर पार्टस	टायर टयूबज और
अम्बाला	3673432.00	1841223.00	4173442.00	2151569.00
गुडगांव	2578556.00	2250583.00	4102974.00	2876841.00
चण्डीगढ	1200197.00	1725602.00	2386106.00	2230546.00
रोहतक	3813655.33	3578232.00	5310842.89	3020648.55
करनाल	3533295.03	1802149.10	3644236.10	1477815.29

हिसार	1911582.00	114222.00	2845150.00	771528.00
रिवाड़ी	1277734.00	1516349.00	1825320.00	2188126.00
जींद	2028725.00	1215297.00	2192151.32	1453989.03
भिवानी	2023864.00	1250764.00	2542147.00	1830043.00
कैथल	1086898.76	626069.88	2279573.73	1380599.78

31.05.1976 को प्रत्येक डिपू के स्टोर/स्टाक में पड़े स्पेयर पार्ट्स, टायरज तथा टयूबज की कुल कीमत

	स्पेयर पार्ट्स	टायर टयूबज और
अम्बाला	2314816.00	124480.00
गुडगांव	766080.00	151066.00
चण्डीगढ़	2302563.00	198996.00
रोहतक	2263748.12	117963.00
करनाल	1757154.31	3.081946.06
हिसार	578296.00	387544.00

रिवाड़ी	933179.00	94239.00
जींद	777438.91	72881.13
भिवानी	1151702.00	151121.00
कैथल	911735.40	101051.87
स्पेयर पार्टस की कुल कीमत		13756712.74
कुल जोड		1672288.38

चौधरी शिव राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने इतना लम्बा चौड़ा कथन रख दिया है जिसको भायद में पढ़ने लगूं तो कम से कम एक घण्टे का समय लग जाए।

Mr. Speaker: This is not the fault of the Minister.

चौधरी शिव राम वर्मा: खैर मैं फिर भी इस पर एक अनुपूरकर प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जो करोड़ों रूपए के पुर्जे 1972-73 से लेकर 1975-76 तक खरीदे गए हैं उनको खदीदने के क्या तरीके हैं? इस तरह तो उस खरीद में काफी गोलमाल हो जाएगा। क्या मिनिस्टर साहिबा बताएंगी कि टायरज और ट्यूबज की खरीद के लिए कोई खरीद लेती है?

श्री प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, इस बारे में भारत सरकार की एक कमेटी बनी हुई है उसके अनुसार चीजों के कुछ रेट्स भी फिक्स किये हुए हैं और सिलेक्ट की हुई फर्मों से हरियाणा रोडवेज पुर्जे मंगवाती है।

चौधरी शिव राम वर्मा: स्पीकर साहब, हरियाणा रोडवेज जो खरीद करती है उसकी चैकिंग कभी मिनिस्टर साहब ने भी की है कि नहीं कि यह खरीद का तरीका उचित है कि नहीं।

परिवहन मंत्री (श्री के. एल. पोसवाल): जी हां।

चौधरी अब्दुर रजाक खां: स्पीकर साहब, क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि जिन फर्मों से माल खरीदा जाता है वे फर्म कहीं

नकली तो नहीं है। कहीं वे हमें डुप्लीकेट माल तो सप्लाई नहीं करती? क्या सरकार कभी इस बात की चैकिंग करती है?

श्री के. एल. पोसवाल: स्पीकर साहब, कोई भी ऐसा डिपॉ नही है जो कि इस साल हमने चैक न किया हो।

चौधरी फूल चन्द (रोहट): स्पीकर साहब, मैं वजीर साहब से यह पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा रोडवेज जो टायर खरीदती है उस एक टायर की कितनी कीमत है और वे टायर किन-किन फर्मों से खरीदे जाते हैं?

श्री के. एल. पोसवाल: स्पीकर साहब, डायरैक्टर जनरल आफ सप्लाइज एण्ड डिसपोजल हमें फर्मों के नाम बता देता हूँ जिन से हम खरीद करते हैं वे फर्में हैं:— मैसर्स सीएट टायर्स प्रिमीयर्स, गुडईयर, फायर स्टोन, इंडियन टायर, डनलप, इन्चेक, मद्रास रबर फैक्टरी इत्यादि। कीमते तो वेरी करती रहती है।

श्री के. एन. गुलाटी: स्पीकर साहब, जब रास्ते में बसें खराब हो जाती है तो उससे सवारियों को बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है क्या सरकार बसों के साथ कोई स्पेयर पार्ट्स वगैरह सप्लाई करने की कृपा करेगी या कोई थोड़ा पैसा हर बस के लिये रखेगी ताकि मौके पर ही बस ठीक कर ली जाए और सवारियों को परे जानी न उठानी पड़े, क्या ऐसी कोई योजना सरकार के विचारधीन है?

श्री के. एल. पोसवाल: स्पीकर साहब, इस बारें में हमने जनरल मैनजरज को इखतियारात दे रखे हैं हमने बड़े पैमाने पर स्टेट लेवल पर सैल बनाये हुए है जो पार्टस वाई करके देते है।

राव बंसी सिंह: स्पीकर साहब, क्या मिनिस्अर साहब बतायेगे कि जो पुराने टायर ट्यूबज है उनको डिपोज करने का क्या तरीका है?

श्री के. एल. पोसवाल: उनको हम नीलाम कर देते है।

श्री गुलाब सिंह जेन: स्पीकर साहब, क्या मिनिस्अर साहब यह बतलाने की कृपा करेगे कि हरियाणा रोडवेज वाले जो टायरज वगैरह की खरीद करते है या यह खरीद मैनुफकचरर्ज से की जाती है या कि इण्टरमीडिएटर्ज से की जाती है?

श्री के. एल. पोसवाल: स्पीकर साहब, हर कम्पनी के अपने डिपोज होते है।

चौधरी दल सिंह: स्पीकर साहब, मिनिस्अर साहब ने अपने उत्तर में यह बताया है कि 31.03.1976 तक 6126 टेस्ट रिपोर्टस पैडिंग थी। तो मैं मिनिस्टर साहब से यह पूछ सकता हूं कि यह जो बकाया टेस्ट रिपोर्टस है ये कितनी कितनी पुरानी पड़ी हुई हैं 6 महीने की कितनी, साल की कितनी और डेढ साल की कितनी कितनी पुरानी है?

**Test Reports for Electricity Connections for
Agricultural Tub wells**

***1619 Ch. Dal Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the total number of test reports for electricity connections for agricultural tube wells pending with the Haryana State Electricity Board as on 31st March, 1976;

(b) the total number of electricity connections given to Agricultural tube wells as referred to in part (a) above are likely to be given to the farmers?

State Minister for Irrigation and Power (Sardar Harmohinder Singh)

(a) 6126

(b) 10063

(c) By the end of current financial year 1976-77

सरदार हरमोहिन्द सिंह चट्ठा: इसमें एक महीन की पुरानी 825 है, तीन महीने की पुरानी 1216 है तीन से छः महीने से उपर की 3018 है।

राव बंसी सिंह: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जो टैस्ट रिपोर्ट्स तीन हजार के करीब छः महीने से ज्यादा पुरानी है, वे कौन से जिले की सबसे ज्यादा है?

सरदार हरमोहिन्द सिंह चट्ठा: जो मेरे पास पैडिंग टैस्ट रिपोर्ट्स की फिगरज है वे सबसे ज्यादा पैडिंग इस प्रकार

है—पहेवा मे 222, करनाल में 354, कुरुक्षेत्र में 474 और रिवाड़ी में 1657

चौधरी फूल चन्द (मुलाना): क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इन पैडिंग टैस्ट रिपोर्ट्स में एम. आई टी. सी और एस. एफ. डी. ए. के ट्यूबवैल्ज कितने हैं और क्या उनको जल्दी कनेक्शन देने की कोशिश की जाएगी?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: हमने एम आई टी.सी. के ट्यूबवैल्ज को हमें प्रायोरिटी दी है। इस वक्त हमारे पास 6 हजार कनेक्शन पैडिंग हैं और हमारे मुख्य मंत्री जी ने यह आदेश दिया है कि इस साल 12 हजार ट्यूबवैल्ज को कनेक्शन देना है और यह फैसला हो चुका है इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास छः हजार टैस्ट रिपोर्ट्स पैडिंग हैं और हम इनको कनेक्शन देने के बाद छः हजार को और फालतू कनेक्शन दे देंगे?

चौधरी रिजक राम: जैसे मंत्री जी ने अभी बताया है कि 6 महीने से ज्यादा और तीन महीने से ज्यादा इतनी इतनी टैस्ट रिपोर्ट्स पैडिंग पड़ी है तो क्या वे इक्विपमेंट की वजह से पड़ी है या पैसे की वजह से पडिंग पड़ी है या कोई और कारण है?

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): अध्यक्ष महोदय, दोनों ही बातें हैं। सामान की भी डिफिकल्टी है और पैसे की भी डिफिकल्टी है और इन दोनों ही कठिनाईयों को दूर करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश गर्ग: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि कल्लर भूमि में जो ट्यूबवैल्ज लगे हुए हैं क्या उनको कनैकाने देने में कोई प्रायरिटी दी जाती है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: जो लैंड रिकलेम होनी है और उस पर कर्जा लेकर ट्यूबवैल लगाया गया है वहां पर तो हम प्रायरिटी देते हैं और जो नहीं है और कोई वेसे ही क दे कि यह लैंड रिकलेम होनी है तो वहां प्रायरिटी नहीं दी जाती।

चौधरी विठ्ठल राम वर्मा: पिछली बार भी यह बात आई थी कि टैस्ट रिपोर्ट्स देने के बाद भी कनैकाने देने को काफी अर्सा लग जाता है और मुख्य मंत्री जी ने यह आवासन दिया था कि हम इस बात को विचारेगे तो क्या इस बात पर कोई विचार किया गया है या नहीं कि जो कनैकाने के लिये एप्लाई करें उसको टैस्ट रिपोर्ट देने से पहले ही यह बता दिया जाए कि आपका नम्बर आने वाला है आप सारा काम मुकम्मल करके रखे?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: यह हमारे लिये पासिबल नहीं है कि जिस वक्त कोई एप्लीकेशन दे उसी वक्त उसे कोई डैड लाइन दे दी जाए। हम यह कोशिश करते हैं कि पिछले साता वर्षों में इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने कनैकाने देने का जो भी टारगेट रखा उससे सवाए या डेढ़ गुना कनैकाने दिये गये।

हमारी यह है कि किसी प्रकार का भी ट्यूबवैल हो लोन लेकर लगाया जाए या अपने पैसे से लगाया जाए उसको जल्द एनराज्ड किया जाए।

चौधरी मेहर चन्द: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जो रिपोर्ट्स एक साल से ज्यादा अर्से से पैडिंग है उनका नम्बर कितना है और उनको क्लीयर करने के लिये क्या सटैप्स उठाए जा रहे हैं?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: मैंने अभी बताया है कि जितनी रिपोर्ट्स पैडिंग है, उनको 6 महीने में खत्म कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: अभी कहा तो है कि सबको दे देंगे।

चौधरी मनफूल सिंह: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जहां 15 सौ से ज्यादा रिपोर्ट्स पैडिंग है, वहां सामान जल्दी भेजा जाएगा?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: इसमें एक दिक्कत आती है कि कुछ एरिये ऐसे हैं जहां लाइनें इतनी बिछ चुकी हैं कि वहां खम्बे भी लग जाते हैं और लोग ट्यूबवैल के लिये बोर भी कर लेते हैं और वह अपना प्रायोरिटी का केस बना लेते हैं और कुछ एरिये ऐसे हैं जहां लाइने दो-दो मील से लेनी पड़ती हैं।

चौधरी रिजक राम: स्पीकर साहब, अभी मुख्य मंत्री जी ने बताया कि गवर्नमैट इन्ट्रैस्ट में रियायत नहीं दे सकती। क्या

उनके नोटिस में यह बात है कि जिन्होंने इस तरह के लोन लिये हुए हैं बैंक्स से या ने एनेलाइज्ड बैंक्स से उनकी कि ते कनैक एन देने से पहले ही डियू हो जाती है जिसको देने में उनको दिक्कत होती है? तो क्या कोई ऐसा प्रोसीजर अडाप्ट किया जाएगा कि पैदावार भुरु होने कुछ अर्से बाद रिकवरी भुरु की जाए?

श्री बनारसी दास गुप्त: अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के केसिज अगर नोटिस में लाए जाएंगे तो हम कुछ लिनिएंसी बरतेगे ।

चौधरी अमीर चन्द कक्कड: क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि अगर कोई 2500 रूपये पहले अदा कर दे जैसे कि पहले स्कीम थी तो क्या उसे कनै एन देने में प्रायरिटी दी जाएगी?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: वह तो दे ही रहे हैं ।

**Cooperative Labour and Construction Societies
in the State**

***1672 Rao Dalip Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the total number of cooperative Labour and Construction societies in the state;

(b) the total amount of loan advanced to the above said cooperative Labour and Construction Societies by the Cooperative Labour and Construction Societies by the

Cooperative Banks in the State during the financial year 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1975-76;

(c) the total amount of the above said loan as is outstanding against the cooperative labour and construction societies to date; and

(e) the total number of cooperative Labour and construction societies which have received Medium Term loan from the cooperative banks in the state during the financial years 1973-74, 1974-75, and 1975-76?

Mr. Speaker: Extension has been asked for in respect of this question which has been granted. The communication received from the Chief Minister is as follows:-

“BANARSI DASS GUPTA

CII-76/3456

Chief Minister, Haryana

Chandigarh

Chandigarh, dated the 6th July,
1976

Subject: Starred assembly question No. 1672 asked by Rao Dalip Singh M.L.A regarding cooperative labour and construction Societies in the State.

My dear Ch. Sahib,

I write to inform you that starred assembly question No. 1672 asked by Rao Dalip Singh, M.L.A, was received in the Secretariat (in cooperation Department) on the 24th June[1976. This question has been fixed for answering on 9th July,

1976. As some information pertaining to this question is yet to be collected, I shall therefore, feel grateful if this question is fixed for answer on any date after the 24th July, 1976.

with regards,

Yours Sincerely,

Sd/-

(BANSARSI DASS GUPTA)

Ch. Sarup Singh

Speaker

Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh.

Constructon of a shed at Ganaur

*1677 Sh. Partab Singh Tiagi: Will the Minister for Transport be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a shed for passengers at Ganaur District Sonapat at G.T. Road and also to appoint a booking clerk there; and

(b) if so, the time by which the afore said proposal is likely to be materialised?

शिक्षा एवं परिवहन राज्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी):

(क) हां

(ख) महा प्रबन्धक को गनौर में यात्रियों की सुविधा के लिए भौड का निर्माण करने हेतु उचित अनुदे 1 जारी कर दिए गए हैं ज्यों ही उक्त कार्य के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध हो जायेगी, भौड का निर्माण करवा दिया जायेगा और इसके बन जाने के बाद वहाँ पर बुकिंग क्लर्क भी नियुक्त कर दिया जायेगा।

श्री प्रताप सिंह त्यागी: स्पीकर साहब, कर्नल महा सिंह जी ने यह अनाउंस किया था कि 5-7 रोज में वहाँ बुकि क्लर्क आ जाएगा और भौड बाद में बनता रहेगा। वहाँ पर प्राइवेट बसिज वाले तो सवारियों को ले जाते हैं लेकिन हमारी बसे वहाँ ठहरती नहीं क्योंकि वहाँ अर्षी तक कोई भौड भी नहीं बना है और न ही कोई बुकिंग क्लर्क लगाया गया है तो क्या मंत्री महोदय 5-10 दिन के अन्दर अन्दर किसी आदमी की नियुक्ति वहाँ कर देगे, भौड बाद में बन जाएगा?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: वहाँ पर एक आदमी लगा हुआ है और जैसे ही हम जमीन एक्वायर कर लेगे वहा पर भौड भी बनवा देगे।

श्री प्रताप सिंह त्यागी: स्पीकर साहब, अभी तक वहाँ पर कोई आदमी नहीं लगाया हुआ है तो क्या मंत्री महोदय इस चीज को मालूम करके वहाँ पर आदमी लगाने की कृपा करेगे?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

Irrigation Through Wester Yamuna Canal System

* **1682 Ch. Shiv Ram Verma:** Will the Chief Minister be pleased to state the percentage of the land under Western Yamuna Canal System to which water was being supplied actually during the financial years 1967-68 and 1974-75 respectively?

State Minister for Irrigation & Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha):

The percentage of the land under western Yamuna Canal system to which water was being supplied actually is as under:-

चौधरी शिव राम वर्मा: यह जो 50 प्रतिशत 1967-68में बताया है और 63 प्रतिशत बताया है 1974-75 में, क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि मौके पर इसी रेटों से सिंचाई हो रही है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: सर, जो हो रही वही बता रहा हूँ।

Mr. Speaker: Question Hour is over.

Remission given to the Life Prisoners

524 Ch. Ram Lal Wadhwa: will the Minister for Transport be pleased to state the total period of remission, if any, given to the life prisoner in each Jail of the state by the Inspector General of Prisons Haryana during the years from 1970 to 1976 (to date) together with the names of such prisoners, separately?

परिवर मंत्री (श्री के. एल. पोसवाल):

इस सम्बन्ध में जो सूचना मांगी गई उसे एकत्रित करने पर जो समय तथा परिश्रम लगेगा उससे विशेष लाभ नहीं होगा।

Remission given to life Prisoner

Remission given to the Life Prisoners

525 Ch. Ram Lal Wadhwa: will the Minister for Transport be pleased to state the total period of remission, if any, given to the life prisoner in each Jail of the state by the Inspector general of Prisons Haryana during the years from 1970 to 1976 (to date) together with the names of such prisoners, separately?

परिवर मंत्री (श्री के. एल. पोसवाल):

इस सम्बन्ध में जो सूचना मांगी गई उसे एकत्रित करने पर जो समय तथा परिश्रम लगेगा उससे विशेष लाभ नहीं होगा।

Loan given under the middle Income Group and Low Income Group Housing Schemes

513. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Finance be pleased to state-

(a) the district wise total amount of loan given under the middle income group and low income group housing schemes separately, during the financial years from 1968-69 to 1975-76 together with the district wise total number of

persons to whom the above said loans have been given, separately; and

(b) the district wise total number of persons who have not paid loan instalment against loans granted as referred to in part (a) above together with the amount involved in each case during the period referred to above, separately?

Finance Minister (Sh. Ram Saran Chand Mittal):

A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

		Distric wise total amount of loand given during 1968-69 to 1975-76		Total No. of persons who were given loan during 1968-69 to 1975-76		Total No. of persons who have not paid loan instalments during 1968-69 to 1975-76		Amount invloved in cased as referred in part (b)	
		Ligh	Migh	Llah	Migh	Ligh	Migh	Ligh	Migh
1	Ambala	2370000	554000	442	50	111	14	124254-86	18686-08
2	Karnal	1062000	339000	397	40	189	17	192454-37	11474-28
3	Kurukshetra	1232000	259000	460	39	367	30	298905-30	70440.31
4	Sonepat	538700	107000	68	8	33		331325.94	

5	Rohat	1867800	404000	439	31	191	5	100965.20	9948.86
6	Narnaul	1160000	400000	235	27	30	9	94636-31	13603.75
7	Jind	1282500	400000	347	32				
8	Bhiwani	2254600	394000	499	32	328	12	297627.00	19935.00
9	Hissar	2764200	1032000	530	67	221	12	300680	28089.00
10	Gurgaon	2440000	600000	530	43	373	6	224448.89	17051.92
11	Sirsa	578000	174000	109	11	60	4	73660.09	12103.80
12	Faridabad	3100.500	3280000	373	184	23	10	18943.00	26886.00
13	Panchkula	101500	165000	7	6				

Haryana Lottery

514 Ch. Ram Lal Wadhaw: Will the Minister for Finance be pleased to state the year wise total unclaimed amount of various draws of Haryana Lottery lying with the Government since 1968-69 to 1975-76, separately?

Finance Minister (Sh. Ram Saran Chand Mittal)

The Yearwise unclaimed amount of prizes is as under:-

Year	Amount (Rupees in Lakhs)
1968-69	0.38
1969-70	4.27
1970-71	13.77
1971-72	5.45
1972-73	9.03
1973-74	6.45
1974-75	4.20
1975-76	4.92

Note: :The amount for the year 1975-76 is provisional as the prizes of 77th Draw held on 30th March, 1976 are still under process of payment

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Transport Minister (Sh. K.L. Poswal): Sir, I beg to move-

That the processdings on the items of business fixed for to day be exempted at this days sitting from the provisions of the rule sittings of the Assembly indefinitely.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the processdings on the items of business fixed for to day be exempted at this days sitting from the provisions of the rule sittings of the Assembly indefinitely.

Mr. Speaker: Question is-

That the processdings on the items of business fixed for to day be exempted at this days sitting from the provisions of the rule sittings of the Assembly indefinitely.

The motion was carried

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Transport Minister (Sh. K.L. Poswal) Sir, I beg to move-

That the assembly at its rising this day shall stand adjourned since die.

Mr. Speaker: Motion moved

That the assembly at its rising this day shall stand adjourned since die.

Mr. Speaker: Question is-

That the assembly at its rising this day shall stand adjourned since die.

The motion was carried

मेज पर रख गए कागज-पत्र

Finance Minsiter (Sh. Ram Saran Chand Mittal)

Sir, I beg to lay on the Table-

The appropriation account of the Government of Haryana for the year 1974-75

The report of the comptroller & Auditor General of India of the Government of Haryana for the year 1974-75

The Finance account of the Government of Haryana for the year 1974-75

The annual Financial statement (Budget Estimate) of the Haryana State Electricity Board for the year 1976-77, as required under section 61 of the Electricity (supply) Act, 1948.

The Development and Panchyat Department Notification No. : G.S.R. 147/P.A. 3/61/S 115 Amd(1) 76 dated the 11th June, 1976, regarding the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads Non Official Members (Payment of Allowances) Haryana First Amendment) Rules, 1976 as

required under section 115 (4) of the Punjab Panchayat Samitis Act, 1961.

The Development and Panchayat Department Notification No. : G.S.R. 24/H.A/30/70/S. 22/Amd. (1) 76 dated the 27th February, 1976, regarding the Haryana Cattle Fairs (First Amendment) Rules 1976, as required under section 22(3) of the Haryana Cattle Fairs Act, 1970.

The Revenue Department Notification No. G.S.Rs. 10/HA. 26/72/S 31//Amd (2)c76 dated the 23rd January, 1976, regarding the Haryana Ceiling on Land Holding (First Amendment) : Rules, 1976, as required under section 31(2) of the Haryana Ceiling on Land Holding Act, 1972

The town and country Planning Department Notification No. G.S.R. 107/HA. 8/75/S. 24/76, dated the 7th March, 1976, regarding the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Rules, 1976, as required under section 24(3) of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975.

विशेषाधिकार समिति के प्रारम्भिक प्रतिवेदन पे आ करना तथा
अन्तिम प्रतिवेदन देने का समय बढ़ाना

Chairman, Committee of Privileges (Sh. Gulab Singh Jain): Sir, I beg to present the fourth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege against the Editor, Printer and Publisher of the Daily New-paper "The Motherland" for publishing news-item in its issue dated the

12th July, 1974. under the caption "Bansi Lal's throne rocked by three incidents."

Sir, I also beg to move-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the 31st March, 1977.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the 31st March, 1977.

Mr. Speaker: Question is—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the 31st March, 1977.

The Motion was carried.

Chairman, Committee of Privileges (Sh. Gulab Singh Jain): Sir, I beg to present the fourth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege against Chaudhri Chand Ram, M.L.A. for making a statement and Sh. Ramesh Chander, Printer, Editor and Publisher of the Daily Newspaper, "Punjab Kesar" for publishing it as also the distorted version of the proceedings of the House in its issue dated 1st December, 1974, under the caption "विपक्ष हरियाणा विधान सभा के भोश अधिवे उन का बाईकाट करेगा।"

Sir, I also beg to move-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the 31st March, 1977.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the 31st March, 1977.

चौधरी रिजक राम (राई): स्पीकर साहब, यह जो मो इन अभी हाउस के सामने पढी हैं, सदन के सभी सदस्यों को पता हैं कि चौधरी चांद राम एक साल से जेल मे डिटेन किए हुए है तो इस इंकवायरी का प्रिविलेज के तौर पर इतना बढा लेना और इसे इतना लम्बा करना उचित मालूम नही होता। इस तरह से इस मो इन को सिर पर लटकाए रखने से कोई फायदा नही हो सकता इसलिए मै चेयरमैन साहब, आपकी मार्फत यह अपील करूंगा कि इस मो इन को अगर वह मैम्बर साहब वापिस ले लें तो अच्छा होगा क्योंकि जो आदमी एक साल से जेल मे बन्द हैं उसके बारे मे बार—बार एक्अें इन मांगनी ठीक नही लगती।

Mr. Speaker: Question is—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the 31st March, 1977.

The Motion was carried.

Chairman, Committee of Privileges (Sh. Gulab Singh Jain): Sir, I beg to present the Third Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege against Sh. Lalit

Mohan, Editor and Sh. Virender, M.A. publisher and Printer of the Daily Newspaper "Vir Partap" Jullunur, for writing derogatory remarks against the house and its Members in its issue dated the 10th January, 1975, under the caption. "चौधरी हरद्वारी लाल का क्या कसूर है।"

Sir, I also beg to move-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the 31st March, 1977.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the 31st March, 1977.

Mr. Speaker: Question is—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the 31st March, 1977.

The Motion was carried.

लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन पे 1 करना

Chairman, Committee on Public Accoutns (Ch. Ishwar Singh): Sir, I beg to present the Tenth Report of the Public Account Commit6tee for the years 1976-77

दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं० 3) बिल, 1976

Finance Minister(Sh. Ram Saran Chand Mittal): Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No.3) Bill, 1976.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Appropriation (No.3) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Haryana Appropriation (No.3) Bill be taken into consideration at once.

चौधरी रिजक राम (राई): स्पीकर साहब, यह जो एंप्रोप्रिए इन बिल हाउस के सामने वित्त मंत्री जी ने अभी पे किया है इसकी कुछ डिमांडज के बारे में मैं अपने कुछ विचार रखूंगा। पहली डिमांड इस सदन के माननीय सदस्यों के बारे में है। इसके द्वारा उनके टी.ए. बिल्ज के लिए जो कंटेनजेंसी फंड से पैसा खर्च किया गया है 250000 रूपये के करीब, उसकी मांग की गई है। वैसे रकम भी कोई ज्यादा नहीं और इसके मंजूर करने में कोई आप्पति नहीं लेकिन एक मैं आपके द्वारा अर्ज करना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन हुए वित्त मंत्री जी ने एक सवाल के जवाब में फरमाया था कि सरकार ने अपने अखराजात में कमी करने के लिए, इकौनोमी करने के लिए, बहुत से कदम उठाए हैं और उस पर इस सदन के माननीय मैम्बर साहेबान ने काफी चेश्टा करके सप्लीमेंटी सवाल भी पूछे थे और यह इच्छा प्रकट की थी कि हरेक खर्च में जो भी आज सरकार कर रही है। उसमें ज्यादा से ज्यादा कमी की जाए।

Sh. Ram Saran Chand Mittal: Sir, I may point out that as per the standing convention, the Vidhan Sabha

demand is not debatable. Although I do not mind the discussion and I am prepared to answer but it will be a departure from the existing convention.

Mr. Speaker: It is a voted item.

Sh. Ram Saran Chand Mittal: No doubt it is a voted item, but the convention is that the Vidhan Sabha Demand is not debated upon.

Mr. Speaker: This item relates to the hon. Member of this house और प्रैसीडेन्ट यही हैं, पहले कन्वैन्शन भी है कि विधान सभा के मुताल्लिक डिस्कशन न हो या कम से कम हों। अच्छा हो यदि मैम्बर साहब इस डिस्कशन को अवायड करें लेकिन अगर करना ही चाहते हो तो कोई ऐसी बात न कहें जिस पर किसी को एतराज हों।

चौधरी रिजक राम (राई): जो वित्त मंत्री जी ने फरमाया मैं इससे बिल्कूल एक लफ्ज इधर उधर नहीं जाऊंगा या रिवायत के खिलाफ नहीं कहूंगा। मैं तो सिर्फ इतना ही अर्ज करना चाहता हूँ कि इस खर्च में जितनी भी ज्यादा से ज्यादा हम बचत कर सकें वह करनी चाहिए। मैं यह समझता हूँ कि टी.ए. के जरिए या जो खर्च इन मीटिंग्स में होता है वह बिल्कूल वही होता है जो अति आवश्यक है कोई फिजूरखर्ची इसमें नहीं। मैम्बर साहेबान अपने दायित्व को, जिम्मेदारी को समझते हैं लेकिन इस बात को समझते हुए, मानते हुए भी, चूंकि आज हमारे सामने बड़े प्रोग्राम है, जवाहर लाल नेहरू कैंनालव ओर लिंक कैंनाल आदि को सवाल है, जब

एक एक मद मे हम बचत कर रहे है तो हम एक मिसाल रखें एक ऐगजाम्पल सैट करे कि जो भी ज्यादा से ज्यादा बचत हम कर सकें वह हम करें कुछ मैम्बर साहेबान यहां है नही इसलिए ज्यादा में नही कहना चाहता लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि एक छोटी सी कमेटी जैसे लाईब्ररी कमेटी है, जो यहां चंडीगढ़ मे बैठ कर काम कर सकती है उसे कलकता बम्बई या दूसरी जगहां के दौरे करने की क्या जरूरत हैं? कैटेलौगज जो दूसरे राज्यों के लाईब्रेरीज के है वे यहा बैठे हुए मिल सकते है, अखबारों में भी वे आत है। मै कोई आक्षेप नही करता लेकिन स्पीकर साहब, आपके द्वारा मै अर्ज करना चाहता हूं कि जो भी कमेटी के दौरे होते है आम तौर पर बाहर जाने के वे आपकी इजाजत से होते है। जो भी बचत इसमें हो जाए वह अच्छी बात है ताकि किसी क्वार्टर से यह चर्चा न हो सके कि इस सदन के मैम्बर अपने दायित्व को निभाने मे कमी रखते है। मै इससे ज्यादा इस बात पर कहना नही चाहतो क्योंकि अगर फिजूलखर्ची होती है तो उसमे मै भी भाामिल हूं। कोई ऐसा नही कि मै अब ऐवरीथिंग हूं। सभी मैम्बर साहेबान मेरे से ज्यादा अपने फर्ज का समझते है और इस कोिाा मे हे कि कम से कम खर्च हो लेकिन फिर भी यह प्रार्थना करूंगा कि जहां तक खर्च मे कमी हो सके करनी चाहिए। इसमे वित मंत्री जी और आप भी काफी सावधी बरत सकते है।

दूसरी बात जो मै अर्ज करना चाहता हूं वह स्पीकर साहब, डिमांड नम्बर 2 के बारे मे है। यह डिमांड नम्बर 2

'इन्फर्मे ान एंड पब्लिसिटी' के बारे मे है। स्पीकर साहब, हमारे प्रान्त मे पब्लिक रिले ांज डिपार्टमेंट काफी विस्तार रखता है, काफी उसकी ऐस्टैब्लि ामेंट हैं। हर डिस्ट्रिक्ट मे डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिले ांज औफिसर हैं, उनके असिसटेंट हैं। उनके पब्लिकसिटी वर्कर्स है जो प्रचार करते है लेकिन एक बात मै अर्ज करना चाहता हूं। जहा तक डिस्ट्रिक्ट मे पब्लिक रिले ांज औफिसर्स का और उनके नीचे के स्टाफ का ताल्लूक है सिवाय मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी के दौरे मे प्रोग्राम की पब्लिसिटी करने से ज्यादा कोई काम उनका होता नही। मै आपको कांफिडेंन्टली यह कह सकता हूं कि कितने ही डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिले ांज औफिसर्स ऐसे है जिन्हे यह पता नही कि इस विधान सभा ने गरीबों की सहायता के लिए क्या क्या कानून पास किए है। कितने ही ऐसे डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिले ांज औफिसर्स है या स्टाफ के मैम्बर्स है जिनको यह मालूम नही कि ऐग्रीकल्चर युनिवर्सिटी हिसार ने या दूसरी यूनिवर्सिटी ने क्या क्या बीज इन्वैन्ट किए है और किसान को किस कीमत पर मिल सकते है। मुख्यमंत्री जी, मैने खुद डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिले ांज औफिसर्स से इसके बारे मे बात चीज की। बिजाई का समय था। मैने उससे कहा कि क्या आप बता सकते है कि चने के लिए, गेहूं के लिए कौन-कौन से बीज मुहैया हो सकते है जो किसान का माफिक है, लेकिन उनका पता नही। फिर मैने पूछा कि जो-जो बिल पिछले सै ान मे विधान सभा ने पास किए क्यसा उनके बारे मे आपको मालूम है कि वे किस महेकमें से और और किन लोगो से ताल्लूक रखते थे

उनका यह भी मालूम नहीं। तो मैं आपके द्वारा स्पीकर साहब, यह अर्ज करना चाहता हूँ कि पब्लिक रिले इंज डिपार्टमेंट को, जो सरकार के कामकाज है, जो उनके प्रोग्राम है, उनसे फुली इक्वीप करना चाहिए। यही नहीं की ये सिर्फ पब्लिसिटी करते रहें। पब्लिसिटी तो दूसरे तरीकों से भी हो सकती हैं पब्लिसिटी तो डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेटिव, पटवारियों की मारफत या दूसरे कर्मचारियों की मारफत भी करवा लेता है। यह कोई इतना जरूरी काम नहीं। देखना यह है कि इस वक्त जो ज्यादा जरूरी काम है, चाहे वह फेमिली प्लानिंग प्रोग्राम का है या चाहे दूसरे प्रोग्राम का है, उसमें आपका पब्लिक रिले इंज डिपार्टमेंट पार्ट प्ले करता है। मैं बिल्कूल दावे के साथ यह कह सकता हूँ कि इस प्रोग्राम में आपका महकम वह काम नहीं कर रहा जो करना चाहिए। एक बात और भी मैं अर्ज करना चाहता हूँ। जहां तक जबानी प्रचार का ताल्लुक है क्या इन्फर्मेशन उसके पास होती है इसके बारे में मैंने अर्ज किया है। अब आप देखें कि दो तीन पत्रिकाएँ पब्लिक रिले इंज डिपार्टमेंट भाया करता है। एक है हरियाणा रिव्यू और दूसरा है हरियाणा संवाद और भी कई इस तरह कि पब्लिक इंज इनकी समय समय पर निकलती रहती है। मैं हरियाणा रिव्यू को भी और हरियाणा संवाद को भी गौर से पढता हूँ। हरियाणा संवाद में, स्पीकर साहब, पढने की तो कोई बात नहीं। उसमें भुरु से आखिर तक देखें तो हर मिनिस्टर की 15-15 फोटो नजर आती हैं।

Mr. Speaker: Order Please. डिमान्ड दो मे इसके लिए कहां खर्चा मांगा गया है?

चौधरी रिजक राम : इसमे दिया है। 'डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव तथा इनफर्मेटिव एण्ड पब्लिसिटी।'

श्री अध्यक्ष : जिन आइटम्ज के लिए सप्लीमेंटरी ग्रान्टस मांगी गई है वे पेज 3 पर दी गई है। चार आइटम्ज के लिए सप्लीमेंटरी ग्रान्टस मांगी गई है। इसमे पब्लिक रिले टान की आइटम नहीं है।

चौधरी रिजक राम : इन्फर्मेटिव एण्ड पब्लिसिटी है।

श्री अध्यक्ष : यह उसमे शामिल नहीं है।

चौधरी रिजक राम : शामिल तो है। Kindly refer to Demand No.2

Mr. Speaker: The details of the items for which the supplementary grants have been asked for are given at page-3. These are—

(i) Expenditure incurred in connection with State Funeral of late Governor Sh. B.N. Chakravarty of Haryana;

(ii) Payment of decretal amount of rent;

(iii) Setting up of Haryana Pavillion at Calcutta; and

(iv) Financial Assistance to Lok Tilak Smark Trust.

Ch. Rizaq Ram: Kindly refer to page.2 It is written—

“Supplementary Estimates of the amount required in teh year ending 31st March, 1977 to defray charges in respect of (i) 212-President/Vice President/Governor/Administrator of Union Territories (2) 253-District Administration and (3) 285-Information and puclicity.”

Mr. Speaker: These are teh sub-heads under which these grants are to be accounted for. The details of the items are given at page 3 where there is no item of expenditure for “Information and Publicity.”

चौधरी रिजक राम : इनफर्मे 11 नव और पब्लिसीटी के लिए एक लाख 65 हजार वोटिड है ।

श्री अध्यक्ष: : यह तो एलोकें 11 आफ सब हैंडज है जिसके अन्दर पैसा पड़ेगा । जिन आइटम्ज के लिए खर्चा मांगा गया है । वह पेज तीन पर दी गई है । इनमे पब्लिक रिले 11 के लिए कोई खर्चा नहीं मांगा गया । इसलिए इस बारे मे डिस्क 11 इरनैलेवैन्ट है ।

चौधरी रिजक राम : अच्छा जी, चलो जी बहुत सी बातें तो आपकी इजाजत से मैंने कह दी । अगर मुख्यमंत्री जी को कोई एतराज न हो तो इस इ 11 के अन्दर एक मंत्री के 15-15 फोटो की बजाए एक ही फोटो आ जाये तो काफी है ।

श्री अध्यक्ष : : आमतौर परा पोसवाल साहब का फोटो फ्रन्ट पेज पर होता हैं। (हंसी)

11.00 बजे

चौधरी रिजक राम : आपको मालूम है और किसी का फोटो आये या न आये परन्तु इनका जरूर आना चाहिए। तो मैं यह चाहता हूं कि इस इ लू के अन्दर किसानो के मुताल्लिक, म िन के मुताल्लिक आना चाहिए। मैं इस डिमान्ड पर ज्यादा नही कहना चाहता हूं।

जहां तक डिमानड नम्बर 15 का सम्बन्ध है उसके बारे मे तो बहुत कुद कहा जा चुका है क्योकि यह डिमान्ड इरीगे ान से सम्बन्धित है। डिमान्ड नम्बर 23 सो ाल वैलफैयर एन्ड रिहैबलीटे ान के बारे मे है। इसमे जो रूपया मांगा गया है वह हरिजनों को प्लाटस देने के लिए और जमीन एक्वायर करने के लिए मांगा गया है। स्पीकर साहब, यह सहारनीय कदम है। इसमे कोई संदेह नही है कि जिन लोगो को सिर छुपाने के लिए मकान नही थे अगर उनको घर बनाने के लिए प्लाटस दे दिये तो सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया है। इस रूपये के देने से किसी को काई आपति नही हो सकती।

मैं आपके द्वारा मुख्यमंत्री जी और राज्सव मंत्री के नोटिस मे एक बात लाना चाहता हूं कि जो कागजात तैयार किये गये है वे सभी कगाजात पटवारी लैवल तक ही तैयार किये गये

है। पटवारी की जिस आदमी के साथ लगती है उसका खेत ले लिया। एक आदमी ने बड़ी मुश्किल से एक किल्ला जमीन खरीदी है उसकी को एक्वायर कर लिया। पटवारी से नीचे के लेवल पर यह सारा कुछ हुआ। अफसरों ने कोई इस बारे में जांच पड़ताल नहीं की। कुछ केसिज तो ऐसे भी हैं जहां प्लॉट्स के लिए जमीन एक्वायर की गई वहां पंचायत या पंचायत समिति की जमीन पड़ी हुई है और नाजायज तौर पर लोगों के कब्जे में है उसको एक्वायर नहीं किया गया और दूसरों की आबपा में वाली एक किल्ला जमीन को एक्वायर कर लिया गया। यह सब उन लोगों ने रंजित निकालने के लिए किया है। उन जमीनों के नोटिफिकेशन हो चुके हैं। वह नोटिफिकेशन बन्द होनी चाहिए। जब उन लोगों ने नोटिफिकेशन बन्द होने की दरखास्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव में दी तो वहां पर कब्जे की नोटिफिकेशन हो चुकी थी। उन्होंने कि अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैं सरकार से यहाँ प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जहाँ पर ऐसे हार्डिप के केसिज हैं, उन लोगों की सहूलियतें मिलनी चाहिए। महज एक रंजित की बजह से या पटवारी के आर्बीट्रेरी एक न के वजह से उन गरीब लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए। एक गरीब आदमी प सारी उम्र मेहनत करके एक किल्ला या आधा किल्ला जमीन खरीदता है और उसको भी लोगों का प्लॉट्स देने के लिए ले लिया जाये तो वह बड़ी भारी हार्डिप है। ऐसे हार्डिप केसिज के अन्दर उन गरीबों को बदले में जीन मिलनी चाहिए। बस, यही मेरी प्रार्थना है।

इरीगे ान मद पर काफी बहस हो चुकी हैं इसमे जो रूपया लिया गया है यह जवाहर लाल नेहरू कैनल के लिए या दूसरे कामों के लिए लिया गया है। यह बहुत अच्छा काम है और यह बहुत जरूरी काम है। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसके साथ ही इस मद से सम्बन्धि मेरी एक प्रार्थना है बहुत छोट छोट काम है। अगर उनके लिए रूपया दे दिया जाए तो बीस हजार एकड़ रकबा आबपो ि हो सकता है। छतहरा बालगढ लिफ्ट स्कीम है। अगर उस स्कीम पर गवर्नमेंट तीन लाख रूपया खर्च कर दे तो आठ दस हजार एकड़ जमीन पर पानी लग सकता हैं तीन लाख रूपये की कमी वजह से सारी जमीन बारानी पड़ी हुई है। इसी तरह से गौरड माईनर स्कीम है। सन 1970 से उस स्कीम पर कोई काम नहीं हुआ। आठ दस गांव है जैसे फरमाना है, सिलाना है ओर दूसरे है सब गावों के रकबे को पानी लग सकता हैं। पचास हजार एकड़ रकबे को पानी लग सकता है। मैने मुख्यमंत्री जी को चिटठी भी लिखी, लोगो की तरफ से भी दरखास्त भिजवायी लेकिन अभी तक तीन लाख, पांच लाख या दस लाख रूपया उन स्कीमों के लिए मंजूर नहीं हुआ। मै तो यह अर्ज करना चाहता हूं कि दूसरी बड़ी स्कीमों पर ज्यादा से ज्यादा रूपया खर्च करें क्योकि उन इलाको की भूमि ज्यादा प्यासी है, ज्यादा पानी की जरूरत महसूस करती है। लेकिन दूसरे इलाकों के लिए किसी स्कीम के लिए एक पैसा भी मंजूर न किया जायें। यह बात ठीक नहीं है। इसलिए मै मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करुंगा कि जो ऐसे केसिज पड़े हुए है उनको भी निकालने की को ि । ।

करें और थोड़ा थोड़ा पेसा उनको दिया जाये। (घंटी) आखिरी आइटम है जिसके बारे में दो लफ्ज मैकहना चाहता हूँ। स्पीकर साहब, फौरेस्ट के बारे में इस एप्रोप्रिएटन बिल में रूपय मांगा गया है, इस आत की मुझे खुशी है। स्पीकर साहब, हमें अपने प्रान्त में ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करके वन लगाने चाहिए। जब से देश आजाद हुआ है जमीन पर अनाज की उपज के लिए ज्यादा भार पड़ा। सरकार की तरफ से इस बात के लिए ज्यादा से ज्यादा दबाव आया कि अनाज के लिए हम जितनी नई भूमि जुटा सकते हैं वह जुटाए। सन 1950 से या फर्स्ट प्लान से कहिए लाखों एकड़ जमीन जिसमें जंगलात थे उसको तोड़कर फसल पैदा की जा रही है और आज हालात यह हैं कि पंजाब तथा हरियाणा में कुल जमीन के दो-तीन परसेंट जमीन में ही जंगलात होंगे जबकि हमारे देश के दूसरे प्रान्त जैसे मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है वहां 50 फीसदी जमीन में जंगलात है। हम जंगलात से बहुत फायदा उठा सकते हैं। स्पीकर साहब, हमारे प्रान्त की बनावट कुछ ऐसी है कि जंगलात की आवश्यकता भी ज्यादा है और इससे हम फायदा भी बहुत ज्यादा उठा सकते हैं। एक इलाका हमारा जो राजस्थान के साथ लगता है वह रेगिस्तानी है। वहां हालात यह हैं कि नहर के लिए खाल खोद कर लोग जाते हैं दूसरे दिन उसका निर्माण बाकी नहीं रहता वह रेत से ढक जाता है। वहां सड़क तक पता नहीं लगता। वह सारी रेत से ढक जाती है। मैं वह इलाका देखा हूँ वहां सैंड डियुन्ज है। उस इलाके में वृक्ष लगाने की बहुत आवश्यकता है। बेसिक आप ज्यादा से ज्यादा भूमि खेती के काम

मे लोए लेकिन कोि । । कीजिए कि जो विलेज रोड़ज है स्कूल है कालिज है। पंचायत समिती के दफ्तर है कितनी ही और जगह है जहां पर वृक्ष लगाए जा सकते है। स्पीकर साहब, हमारे यहां कई प्रकार के इलाके हे। हमारे एक इलाका रेगिस्तानी है। वहां पर आधियां चलती रहती है। वहा पर वृक्ष लगाकर जो रेत उड़ती रहती है। उसको रोका जा सकता है। एक गुड़गांवा मे फिरोजपुर झिरका का इलाका है। इधर अम्बाला मे कुछ पहाडी इलाका है कुछ नदी नालो का इलाका है। लेकिन देखने मे यह आता है कि जितने भी पहाड़ है वे बैरन वहा दरखत नही है। वहां दरखत ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए। दूसरे इलाको मे भी इस तरह की कोि । । करनी चाहिए। स्पीकर साहब, मै ज्यादा न कहते हुए आपके द्वारा प्रार्थना करना चाहता हूं कि गुड़गावा के रोहतक के या सोनीपत के आसपास के इलाके है वे दिल्ली के नजदीक होने के नाते हमे कमि रियल बेसिज पर वृक्ष लगाकर फायदा उठाना चाहिए। जंगलात कटने से गरीब लोगो भूमि पर जंगलात लगाए जाएंगे यह एक अच्छा डिसिजन है। पहले जब जंगलात थे तो गरीब आदमी मेवे ि रखकर अपना गुजारा कर लिया करता था लेकिन अब चरागाह ने होने के कारण गरीब आदमी प गुपालन नही कर सकता। एक तरफ तो हम डेरी डिवेलपमेंट पर जोर दे रहे है और दूसरी तरफ चरागाह नही है जिनव पर लोग प गुपालन नही कर सकता। जंगलात का जहां तक ताल्लूक है मेरी तजवीज है कि यह काम सिर्फ फारैस्ट डिपार्टमेंट पर ही छोड़ा जाए बल्कि जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे

वह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, चाहे एजुकेशन है स्कूलज है क्लासिज है, पंचायत के दफ्तर है, सब को दरक्षता लगाने में हिस्सा लेना चाहिए ताकि इकानामिक फायदा हो, कमिश्नरियल फायदा हो और दूसरे फायदे भी हों।

चौधरी पीर चन्द (बरवाला अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, मैं इस बिल की डिमान्ड न. 13.

Mr. Speaker : Order please. Day before yesterday I had to adjourn the House earlier as no member rose to speak on day. You can only speak on the principles of the Bill. कोई मैम्बर उस दिन बोलने के लिए उठा नहीं। दो तीन घंटे पहले हाउस ऐडजर्न करना पड़ा।

चौधरी पीर चन्द: स्पीकर साहब, मैं यह कोशिश करूंगा कि बिल पर ही बोलू।

Mr. Speaker : Order Please. The time limit has been fixed. पांच पांच मिनट के लिए बोलें। टाइम फिक्स किया हुआ है। एक घंटे का टाइम फिक्स किया हुआ है।

चौधरी पीर चन्द: अध्यक्ष महोदय, इस बिल के द्वारा मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इसके अन्दर समाज कल्याण विभाग को जो रकम दी गई है यह बहुत अच्छा काम है और सराहनीय है इसके लिए मैं आपके द्वारा मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ और इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि

यह रकम सिर्फ प्लाटों के लिए या चौपालो मुरम्मत के लिए दी गई है इससे कोई हरिजनों का भला नहीं हाने जा रहा है। हमारी प्रधान मंत्री जी ने जो 20 सुत्री कार्यक्रम हरिजना तथा गरीब लोगो की भलाई के दिया है और कहा है कि इन लोगो को कुछ उत्साह दिया जाए, इन्हे अपने पांव पर खड़ा होने दिया जाए लेकिन इससे मैं समझता हूं कि कोई भला नहीं हो सकता। कोई रचनात्मक काम होना चाहिए। इनको किसी किस्म का रोजगार दिया जाए, रोजगार के लिए कुछ सुविधाएं दी जाए। या तो उनको जमीन दी जाए अथवा कोई इण्डस्ट्रीज दी जाए और या उनको मुलाजमत दी जाए। लेकिन इसके अन्दर वह बात हुई जैसे कि एक वृक्ष को लगाया जाए और उसे पानी भी दिया जाए लेकिन दूसरी तरफ उसकी जड़ो को काट दिया जायें। तो स्पीकर साहब, इस तरह की ये सरी बातें होती हैं क्योंकि अभी 5 मई 1976 को चीफ सेक्रेटरी साहब का एक आर्डर निकला है। उसमें उन्होंने तमाम वैकनसीज में हरिजनों को एडहाक बेसिज पर लगाने के लिए बैन कर रखा है। इस बारे में हर डिपार्टमेंट के अन्दर यह चिट्ठी पहुंची कि किसी भी हरिजन को एडहाक बेसिज पर न रखा जाए। रिजर्व बेसिज पर आई कोई रिजर्वे नही है।

Mr. Speaker : Order Please. No, I will not allow this things (Interruptions) What are you criticising? इसके अन्दर सिर्फ दो आइटम्ज हैं उसमें आने गवर्नमेंट को धन्यवाद देना हैं।

चौधरी पीर चन्द: स्पीकर साहब, मै क्रिटीसीजम नही कर रहा हूं। मै तो केवल आपके द्वारा अपनी बातें सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं।

चौधरी फूल चन्द (रोहट): स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। चूंकि आप डिमान्डज पर बोलने की इजाजत दे रहे हैं अगर आप ऐसा ठीक नहीं समझते तो आप कम से कम हमें कुछ गाइड लाईन्स दे दें ताकि हम उन के मुताबिक बोल सकें।

राव निहाल सिंह: स्पीकर साहब, आपने उन्हें अंग्रेजी में हा है ओर वह यह समझ बैठे कि जो कुछ वे कह रहे हैं, ठीक है (हंसी)

चौधरी पीर चन्द: स्पीकर साहब, मै तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। आप इस मांग के जरिये सारी पालिसी, सार हरिजनों के मुताल्लिक और सारे डिपार्टमेंट को क्रिटीसाइज नहीं कर सकते।

चौधरी पीर चन्द: स्पीकर साहब, यह दो नम्बर डिमांड भी तो है, इस के मुताल्लिक तो मैं कह सकता हूं।

Mr. Speaker : Order Please. This is not general discussion on Budget. This is a demand. The demand includes only two items. Then What are you Criticising? (Interruptions) I will not allow general discussion.

चौधरी पीर चन्द: स्पीकर साहब, ठीक है, अगर आप मुझे बोलने की इजाजत नहीं देते तो मैं बैठ जाता हूँ। हम पर जो अत्याचार होता हो अगर आप उसके बारे में नहीं कहने दें तो

Mr. Speaker : I will not allow this debate like this. The notification has got no relevancy with the Appropriation Bill.

चौधरी पीर चन्द: स्पीकर साहब, आप कम से कम मेरी बात तो सुने मेरा कहने का मतलब यह है कि (विघ्न)

Mr. Speaker : If you are to be irrelevant, then you please resume your seat.

चौधरी विठ्ठलराम वर्मा (नीलोखेड़ी): स्पीकर साहब, हरियाणा विनियोग विधेयक 1976 के बारे में जिस पर यहां चर्चा चल रही है, उस पर बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ। मैं कोई ज्यादा लम्बी चोड़ी बातें नहीं कहूंगा अगर थोड़ा बहुत इधर उधर कह भी जाऊ तो आप मुझे रोक न लगाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं सबसे पहले मांग नम्बर 2 और 3 के बारे में कुछ कहूंगा। सामान्य प्रशासन और गृह विभाग चूंकि दोनों ही मुख्यमंत्री महोदय के पास हैं इन दोनों के बारे में मैं इक्की ही चर्चा करूंगा सारी बातें इनके बीच में ही आ जाती हैं। अतः इस में मुख्य मंत्री महोदय जितना भी ध्यान दें वह बड़ी अच्छी बात है। इस बारे में स्पीकर साहब, मैं एक दो उदाहरण देना चाहता हूँ।

पहली तो यह कि मेरी डाक गृह विभाग ने रोक रखी है ओर इस मे कोई न्याय की बात नहीं है। हमने पिछले दिनों करनाल मे जो हरियाणा जनसंघ की कार्य समिती की एक मीटिंग बुलाई थी, उसमे कोई ऐसी गुप्त बात तो थी नहीं लेकिन फिर भी पत्र रोक लिये गये जहां जहां भेजे थे नहीं पहुंचे।(विघ्न)

श्री रामसरन चन्द मितल: स्पीकर साहब, डिमांड नम्बर 2 और 3 दोनो मे ही ऐसा कोई जिकर नहीं है, जिस पर ये बोल रहे हैं। Sir, it has nothing to do with the demand under discussion.

चौधरी शिवराम वर्मा (नीलोखेड़ी): मितल साह तो ठीक है हम कुछ भी नहीं कहते (ओर) तो स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि करनाल मे हमने एक मीटिंग बुलाई थी। . . . (विघ्न)

Mr. Speaker : Order Please.

चौधरी शिवराम वर्मा (नीलोखेड़ी): स्पीकर साहब, मैं तो केवल दो या तीन मिनट ही बोलूंगा।

Mr. Speaker : Order Please. It is not a Question of two minutes or ten minutes. The Question is as to what you can say on this and what you cannot say. जब आपको बोलने के लिये अलाउ किया गया तो आप सिर्फ उन आईटमज पर बोल सकते है जोकि इन मे शामिल है। सारे बजट को क्प्रिटिसाइज नहीं कर सकते।

चौधरी िवराम वर्मा (नीलोखेडी): स्पीकर साहब, मैं क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहा हूँ। मैं गृह विभाग के बारे में बोल रहा हूँ स्पीकर साहब, इस विभाग में कुछ सुधार की जरूरत है। इसमें सरकार की बदनामी होती है। स्पीकर साहब, मुझे इस बात की जानकारी भी मिली है कि यहां से कोई टेप रिकार्डर भी गया है। इस बात की जांच पड़ताल होनी चाहिए। एक और बात जिसका मुझे पता चला है वह मैं मुख्य मंत्री महोदय के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि दादरी में एक भाराब की दुकान पर झगड़ा हो गया और इनकी पार्टी के किसी सदस्य की वजह से ऐसा हुआ, इस बारे में जांच पड़ताल होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरी बात स्पीकर साहब, पिपली रेसअ हाउस में भी इनके मन्त्रिमण्डल के एक सदस्य के मुँह पर एक भाराबी ने थप्पड़ भी मारा। इसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिये। स्पीकर साहब, मैं इसलिये कह रहा हूँ कि इस में सरकार की बेइज्ती है।

Mr. Speaker : Order Please. Order please. This is not relevant to this bill. How can I allow all the irrelevant things to be brought in this discussion?

चौधरी िवराम वर्मा (नीलोखेडी): स्पीकर साहब, मेरा कहने का मतलब यह था कि इस से सरकार की बदनामी होती है।
(विघ्न)

श्री रामसरन चन्द मितल: स्पीकर साहब, यह तो सारी बातें एक्सपंज होनी चाहिये।

चौधरी विठ्ठलराम वर्मा (नीलोखेड़ी): स्पीकर साहब, इससे आगे मैं इण्डस्ट्रीज के बारे में कुछ कहूंगा कि काटर और विलेज इण्डस्ट्रीज को सरकार को प्रैफरेंस देनी चाहियें। बड़ी तथा मध्यम इण्डस्ट्रीज को भिन्न भिन्न स्थानों पर फेलाया जाये और इसी तरह की एक योजना नीलोखेड़ी के लिये भी बनाई जाए।

कृषि विभाग के बारे में डिमाण्ड नम्बर 17 पर तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरकार को रोग-रहित बीज देने पर ध्यान देना चाहिये और खेतों में रोगों की रोक-थाम के लिये उपाय किए जाने चाहियें। स्पीकर साहब, इससे आगे डिमाण्ड नम्बर 13 के बारे में केवल इतना ही कहूंगा कि जहां हरिजनों को प्लाटस दिये गये हैं वहां उनको मकान बनाने के लिये वित्तीय सहायता भी दी जाए। अगर तो ऐसा किया गया तब तो ठीक है प नहीं तो सो गल वैलफेयर वहां का ही पड़ा रह जाएगा।

इरीगे टन के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। यदि सरकार में वह इतना नहीं है क्योंकि जब हमारा ए योरड सिंचित होगा तब हम समझेगे कि पानी है और उससे लोगों को ज्यादा लाभ पहुंच सकता है।

फारेस्ट के बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश के अन्दर बहुत सी भूमि कल्लर भूमि के रूप में पड़ी है जिस थूर भी कह सकते हैं, वह खेती के काबिल नहीं है इसलिये उनके अन्दर जंगलात लगाए जाएं। अगर सरकार उसमें

जंगलात लगा कर उसे जमीन के मालिको को सोंप देगी तो जहां मालिको को उससे लाभ होगा वहां उससे प्रदे 1 की दौलत बढेगी ।

एक आखिरी बात मै एक मिनट मे कह कर बैठ जाऊंगा और वह एनीमल हसबैंडरी के बारे मे है। प 10-पालन की तरफ भी पूरा ध्यान दिया जाना चाहिये। अगर इस तरफ ध्यान न दिया गया तो किसान का केवल खेती से ही गुजारा होने वाला नही है इसलिये इस तरफ भी बहुत भीघ्रता से ध्यान दिया जाना चाहिये। बहुत से प 10 बेकार प 10ओं के नाम से हमारे प्रदे 1 से बाहर जाते है। अगर इनकी नसल सुधारी जाए तो इनसे भी बहुत लाभ मिल सकता है। दूसरी चीज प 10ओ के इलाज के लिये डिस्पेंसरियां गांव गांव मे होनी चाहिये क्योकि एक आदमी अगर बीमार हो जाता है तो उसे तो बाहर ले जाया जा सकता है लेकिन प 10 को बाहर नही ले जाया जा सकता है तो उसमे काफी कठिनाई होती है। इसलिये इनके लिये घर मे ही इन्तजाम होना चाहिये। इन भाब्दों के साथ मै आपसे निवेदन करूंगा कि जो सुझाव मैने दिये है उनक पर सरकार गौर करें।

मुख्यमंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): अध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रिए 1ान बिल पर बोलने के लिये एक घंटा दिया गया था।

श्री अध्यक्ष: अब मैम्बर साहेबान से 5-5 मिनट से खत्म करें।

चौधरी प्रताप सिंह दोलता: स्पीकर साहब, मैं सिर्फ दो मिनट लूंगा। स्पीकर साहब, मैं पहला मिनट तो उस डिमांड की तरफ अर्ज करूंगा जो अपनी विधान सभ के एक्सीपेंडीचर के बारे में है। मैं इस पर ज्यादा कुछ न कहते हुए यह कहूंगा कि इसमें थोड़ा सा एक्सीपेंडीचर ज्यादा कर दिया जाए क्योंकि हरियाणा में लैजिसलैटर्ज इनकलूडिंग मैम्बरज आफ पार्लियामेंट के, आपको तो बड़ा तजुरबा है। आप घूमे हैं और आपने देखा है कि सिवाए तीन छोटे मुल्कों से, बाकी सबसे लो-पेड-मैम्बरज है ये वे मैम्बरज हैं जिन में सावरनिटी ले करती है। चौधरी हरद्वारी लाल जेल में हैं यहां नहीं हैं। तो हस्पताल में एक मैम्बर फार्म भर रहा था। जब उस फार्म में उसने तनखाह पांच सौ भरी तो नर्स ने कहा कि “बस” और वह हैरान हुई कि इसके पीछे इतने आदमी क्यों फिर रहे हैं? यह क़िफायत सिर्फ पंजाब और हरियाणा में हो रही है। मेरे जो साथी जेलों में डिटेड हैं, उनको गवर्नमेंट ने खुद ही से वहां नहीं भेजा। बदकिस्मती से ऐसी पोलिटीकल सिचूएशन डिवैल्प हो गई कि कुछ गैर जिम्मेदार आदमियों ने इलैक्टड आदमियों का पीटना शुरू कर दिया और इलैक्टड मिनिस्टर्स का मर्डर करना शुरू कर दिया। यह बदकिस्मती की बात है। किफासिस्अ ताकत सिविल लिब्रटीज को सप्रैस करने में कामयाब हुई। यह कोई प्लेजेंस अफेयर नहीं है कि इलैक्टड मैम्बरज तो जेलों में हो और हमारे दुःख मन इस चीज के लिये कामयाब हों। जो लोग जिनकी सिविल लिब्रटीज डिप्राइव्ड है जैसे चौधरी चांद राम जी हैं उनका कोई कारखान नहीं है चौधरी देवी लाल की तरह से

कोई जमीन और बैंक बैलेंस नहीं है। उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। सिवाए पंजाब और हरियाणा के बाकी स्टेट्स के जो मैम्बर जेल में हैं सबको उनके पूरे अलाउंस मिलते हैं उनकी एबसैंस में सिर्फ दस रूपए टोकन के तौर पर कटते हैं। इसलिये मैं चीफ मिनिस्टर साहब से रिकवैस्ट करूंगा कि इन लोगों को अलाउंस जरूर मिलने चाहिये। दूसरे इस बारे में मैं यह कहता हूँ कि जहाँ तक लाईब्रेरी कमेटी का ताल्लूक है यह कमेटी का खुद आमद की कि इस कमेटी को जाने दें। इस बार यह कमेटी जाएगी क्योंकि हमने लिबर्ली सब लाइंज पर डिवैल्पमेंट करनी है। गुजराती किताबें भी हम लेंगे, महाराष्ट्रीयन किताबें भी हम लेंगे और बंगाल किताबें भी हम लेंगे तो इस प्रकार का यह हमारा प्रोग्राम है। अगर किसी ओर मैम्बर ने मदद देनी हो तो हम उसको भी स्पैशियल इनवाइटी के तौर पर ले जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: चौधरी रिजक राम अगर आपकी तरफ न देखें तो(हंसी)

चौधरी प्रताप सिंह दोलता: दूसरी बात मैं अफारैस्टे गान के बारे में कहना चाहता हूँ। मेरे पास यह महकमा 8 महीने रहा था, मेरा तजरबा है। मुझ से कामरेड डांगे हंसने लगे कि यह महकमा क्या लिया? हरियाणा में न तो मच्छी होती है और न ही द्रखत लगाने की कोई जगह है, महकमा मिला तो क्या मिला? मैं गवर्नमेंट को कहता हूँ कि पहले बहुत अच्छी ट्रेडी गान्ज थी जो अब खत्म हो गई है। आप सबको रुरल बेक ग्राउंड का पता है कि

जो आदमी मरता था मरने से पहले वह पांच द्रखत जरूर लगा कर जाता था और फिर उसकी ओलाद उनकी अच्छी तरह से हिफाजत करती थी। मुझे यसाद है कि एक दफा किसी ने किसी के एनसैस्ट्रल नी का द्रखत काट दिया और उसके लिये तीन मर्डर हुए और मैं उस केस में हाई कोर्ट की स्टेज तक एसोसिएटिड रहा। फिर इसका बदला लेने के लिये तीन आदमीयों को सजा हुई जिनसे दो को उम्र कैद हुई और एक को फांसी हुई तो वह ट्रेडी इन तो अब खत्म हो चुकी हैं फिर कन्सोलीडे इन डिपार्टमेंट कि जरिये से जो अलाटमेंट की गई उसने वह कुल्हाड़ा चलाया कि रूरल एरिये के तीन चौथाई द्रखत खत्म होते चले गये और फिर गोंडा और घोर चलाया जो थे उनके दोनों तरफ के भी द्रखत हो गए। उसके बाद गजब तब हुआ जब विलेज कामन लैंड की डैफीनी इन में न सिर्फ पंचायत को लैंड वैस्ट हुई बल्कि वह छोटे छोटे जोहड़ जो किसानों ने अपने खेतों में प्लुओ को पानी पिलाने के लिये छोड़े हुए थे वे भी बर्बाद हो गए। जब उस जमीन का बंटवारा हुआ तब या तो वह जमीन गांव में वैस्ट कर गई या पंचायत में वैस्ट कर गई अगर तो वह पंचायत में वैस्ट कर गई तब तो पंचायत वालों ने वहां से द्रखत काट लिये और अगर बच गई तो वह लोगो ने काट लिये। इस वजह से छोटे छोटे खुबसूरत द्रखत भी खत्म हो गये। तो मैं अर्ज करूंगा कि इस डिपार्टमेंट को हरियाणा में बहुत काम है और इसकी बहुत आवश्यकता है। मेरी समझ में नहीं आता कि सड़कों के किनारों जहां द्रखत लगाए जा सकते हैं क्यों नहीं लगाये जाते। मुझे इस महकमे के कर्मचारी

और मिनिस्टर साहब इस बात के लिये माफ करें कि इस महकमे के पास और कोई बड़ा काम नहीं है लेकिन अगर ये सड़क के दोनो किनारो पर और रेल की पटरी के दोनो और भी द्रखत न लगा सकेगे तो और क्या करेंगे? अब विलेज कामन लैंड वैस्ट पड़ी है उस जगह पर भी द्रखत लगाए जा सकते है। अगर ऐसा जो जाएगो तो यह भी आपके रूरल डिवैल्पमेंट के प्रोग्राम मे भामिल हो जाएगा अगर ऐसा हो जाएगा तो यह भी आपके रूरल डिवैल्पमेंट के प्रोग्राम मे भामिल हो जाएगा। वजीर साहब मेरी बात को नोट कर लें कि किसी भी सड़क का किनारा और कोई भी रेल की पटरी ऐसी न रहे जहां द्रखत न हों। इन भाब्दों के साथ मै आपका भुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह लेता हूं।

वित्तमंत्री (श्री राम सरन चन्द मितल): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री एस्टीमेटस मे जैसा कि आपने अभी फरमाया था कि जब डिमांड डिसकान मे आयी थी और जब सदस्य उन पर विस्तान से बोल सकते थे तब उन्होने उस अवसर का लाभी नही उठाया और आज एक रिस्ट्रिक्टड सबजैक्ट पर बोलना इनता मुनासिब नही था। चौधरी रिजक राम के जवाब मे मै एक आईटम पर कुछ अर्ज करना चाहता हूं जो कि डिमांड नम्बर 1 के बारे मे है। यह जो डिमांड है अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के बारे मे है। उन्होने कहा कि इस के खर्चे मे इकनामी होनी चाहिए। वित्त मंत्री ने इकानामी का संदे 1 दिया था। जहां तक वित्त मंत्री या वित्त मंत्रालय का सम्बन्ध है उसके खर्चे के बारे मे जवाब देने का

जिम्मेदार हूं लेकिन जो विधान सभा की आइटम होती है जो स्पीकर साहब, मैं खुद स्पीकर रह चुका हूं मैं भी इस पर डिस्कान अलाउ नहीं करता था इसलिए इस पर डिस्कान नहीं हो सकती। चौधरी रिजक राम कहते हैं कि वह कमेटी गयी थी और चौधरी प्रताप सिंह दौलता कहते हैं कि गयी नहीं। अब इस बात का जवाब कौन देगा वेसे मैं अर्ज करता हूं जो कूपनज रेलवे के होते हैं उसका पैसा देना पड़ता है। यह तो हाउस का एक्ट है कि 16 हजार किलोमीटर ट्रैवल करने को आप फाईनैलियल इयर में हक रखते हैं। हम इसमें भी कुछ कट नहीं लगा सकते।

दौलत साहब ने कहा 500 रुपये जो मैम्बर का अलाउंस है यह कम है लेकिन स्पीकर साहब, मुझे याद है कि जब चौधरी बंसी लाल चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने 300 रुपये का जो अलाउंस था उस वक्त उसे इंक्रीज किया था तो उस पर भी बड़ा क्रिटिसिज्म किया गया था कि साहब यह नहीं बढ़ाया जाना चाहिये। तो उस वक्त यह प्रोवीजन रखा था कि जो मैम्बर इंक्रीजड अलाउंस लेना चाहे वह अपना डिक्लेरेटन दे दे और उसको ज्यादा मिलेगा लेकिन आप हैरान होंगे कि जिन्होंने नुक्ताचीनी की उन लोगो ने भी डिक्लेरेटन दिये और सब ने ऐनहैंस्ड अलाउंस लिया। इसी तरह स्पीकर साहब, अगर हम अब बढ़ायेगे तो कई मैम्बर साहबान कहेगे कि यह नहीं बढ़ना चाहिए लेकिन जब लेने का सवाल आयेगा तो सभी ले लेंगे।

एक और सवाल चौधरी शिव राम वर्मा ने उठाया था कि प्लॉट्स तो हरिजनों को दिये जा रहे हैं लेकिन उनको घर बनाने के लिए फाईनैन्सियल असिस्टेंस नहीं दी गई जो कि सरकार को देनी चाहिए। इसके सम्बन्ध में हमारे मुख्यमंत्री साहब ने हाउस में प्लेन बर्डज में कहा था कि गवर्नमेंट कुछ इन्तजा कर रही हैं उनका कुछ न कुछ इमदाद जरूर मिलेगी। पशुपालन के मुताल्लिक भी कुछ कहा गया था इस संबंध में मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिए कोई लम्बी चोड़ी डिमाण्डस नहीं है। पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने बाहर से सांड मंगाए हैं। वे बहुत कीमती हैं और पशुओं के सीमैन का आर्टिफिशियल इनसैमीनेशन करवा कर गायों का दूध बढ़ाने के लिए स्टैप्स लिए जा रहे हैं। इस तरह उनकी नस्ल इम्प्रूव की जा रही है। हर देहात में पशुओं की नस्ल को इम्प्रूव करने के लिए आर्टिफिशियल इनसैमीनेशन सेंटर खाले जा रहे हैं। इसके अलावा और कोई ऐसा प्वायंट नहीं जिस का जवाब देने की जरूरत हो। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को पास किया जाए।

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Appropriation (No.3) Bill be taken into consideration at once.

The Motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will take up the bill clause by clause.

Clauses 2 & 3

Mr. Speaker: Question is—

That Clauses 2 and 3 stand part of the Bill.

The Motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker: Question is—

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The Motion was carried.

Clauses 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clauses 1 stand part of the Bill.

The Motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of
the Bill.

The Motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the title of the Bill.

The Motion was carried.

Finance Minister (Sh. Ram Saran Chand Mital):

Sir, I beg to move—

That the Haryana Appropriation (No.3) Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion Moved—

That the Haryana Appropriation (No.3) Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Appropriation (No.3) Bill be passed.

The Motion was carried.

दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (सैकिण्ड अमैडमैंट) बिल, 1976

Excise and Taxation Minister (Sh. Shyam Chand):

Sir, I beg to introduce the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Bill, 1976.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion Moved—

That the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is

That the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

The Motion was carried.

Mr. Speaker: Now the house will take up the bill Clause by Clause.

Sub-Clauses (2) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Sub-Clauses (2) of Clause 1 stand part of the Bill.

The Motion was carried.

Clauses 2 to 6

Mr. Speaker: Question is—

That Clauses 2 to 6 stand part of the Bill.

The Motion was carried.

Sub-Clauses (1) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Sub-Clauses (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The Motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The Motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the title of the Bill.

The Motion was carried.

Finance Minister (Sh. Ram Saran Chand Mital):

Sir, I beg to move—

That the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion Moved—

That the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Bill be passed.

The Motion was carried.

दि पंजाब कोआप्रटिव (हरियाणा सैकिड अमेंटमेंट) बिल, 1976

State Minister for Home and Health (Smt. Sharda Rani): Sir, I beg to introduce the Punjab Cooperative Societies (Haryana Second Amendment) Bill, 1976.

Mr. Speaker: There is a notice of motion for disapproval from Sh. Shiv Ram Verma and Sh. Ram Lal. If the House agrees the resolution regarding disapproval of the Punjab Cooperative Societies (Haryana Second Amendment) Ordinance, 1976 (Haryana Ordinance No.2 of 1976) and the motion that the Punjab Cooperative Societies (Haryana Second Amendment) bill be taken into consideration at once be discussed together are voted upon separately.

Voice: Yes

चौधरी शिव राम वर्मा (नीलोखेंडी): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसके बारे में जो डिस्ऐप्रूवल का नोटिस दिया है उसको मैं अभी पढ़ देता हूँ उसके कारण क्या यह मैं बाद में बताऊंगा।

मैं प्रस्ताव करता हूँ—

That this House disapproves the Punjab Co-operative Societies (Haryana Second Amendment) Ordinance, 1976 (Haryana Ordinance No.2 of 1976).

Mr. Speaker: Motion Moved—

That this House disapproves the Punjab Co-operative Societies (Haryana Second Amendment) Ordinance, 1976 (Haryana Ordinance No.2 of 1976).

Mr. Speaker: Question is

That this House disapproves the Punjab Co-Operative Societies (Haryana Second Amendment) Ordinance, 1976 (Haryana Ordinance No.2 of 1976).

Shrimati Sharda Rani: Sir, I beg to move—

That this House disapproves the Punjab Co-Operative Societies (Haryana Second Amendment) Ordinance, 1976 (Haryana Ordinance No.2 of 1976).

Mr. Speaker: Motion Moved—

That this House disapproves the Punjab Co-Operative Societies (Haryana Second Amendment) Ordinance, 1976 (Haryana Ordinance No.2 of 1976).

चौधरी विठ्ठल राम वर्मा (नीलोखेंडी): अध्यक्ष महोदय, इस बिल के जरिए प्रिंसिपल एक्ट में काफी संशोधन किए गए हैं। इसकी नम्बर (2) क्लॉज आप देखें। प्रिंसिपल एक्ट का जो पीछे ऐक्सट्रैक्ट दिया गया है उसमें इस संशोधन के बारे में क्लॉज दो के संशोधन के बारे में कोई ऐक्सट्रैक्ट नहीं दिया गया क्योंकि इसमें लिखा है कि:—

“2. After clause (1) of section 2 of the Punjab Co-Operative Societies Act 1961 (hereinafter referred to as the principal Act), the following clause shall be inserted, namely;—”

इसका ऐक्सट्रैक्ट चूंकि नहीं दिया इसलिए मुझे पता नहीं लगा कि असल में एक्ट में क्या है और अब यह क्या संशोधन

लाया जा रहा है। तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि पूरी तरह से जानकारी नहीं दी गई है। इससे आगे क्लोज (3) है। यह लोकतंत्र के थोड़ा विरोध में जाती है क्योंकि रजिस्ट्रार को ज्यादा पावर दी जा रही है। डेमाक्रेटिक सैट अप जहां हों, वहां पर तो लोगों का अपनी मर्जी से काफी हद तक काम करने दिया जाता है। चूंकि इसमें यह बात नहीं है इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ।

इस अमेंडिंग बिल की चौथी क्लोज में तो बहुत सी बातें कही गई हैं। (2) (ए) में भोयर कैपिटल के नाम पर तीन डायरेक्टर्स सरकार बनाएगी अपनी तरफ से। फिर (बी) में एम्प्लायर के नाम पर तीन बनेंगे। उससे आगे (सी) है। इसमें फाईनैन्स कार्पोरेट्स का एक होगा। उससे आगे (डी) है। इसमें इण्डस्ट्रियल फाईनैन्स कार्पोरेट्स का और किसी और सैन्ट्रल फाईनैसिंग इंस्टीट्यूट का नाम पर तीन होंगे। फिर उससे आगे (ई) है। इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट के नाम पर दो और नोमिनेट कर दिए जाएंगे। जब सारे मैम्बर्स तो इस तरह से बना लिए जाएंगे तब वहां लोकतंत्र क्या रहेगा? स्पीकर साहब, यही नहीं एक और बात भी की जा रही है। (एफ) में कहा गया है कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर भी सरकार बनाएगी जो आई.ए.एफ. होगा, या एच.सी. हागा या कोई इसी तरह का दूसरा ऑफिसर होगा। इस तरह से लोकतंत्र की भावना जो है वह इसमें समाप्त कर दी गई है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ या तो इसको सुधारा जाए नहीं

तो सरकार इसको वापिस ले ले या फिर आपके द्वारा माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि इसको वे अस्वीकृत कर दें ताकि इसको ठीक करके दुबारा लाया जा सकें।

चौधरी रिजक राम (राई): स्पीकर साहब, यह जो अमेंडिंग बिल है इससे ज्यादा विरुद्ध कोई क्विबल कोआप्रेटिव के कार्यमूवमेंट का सवाल है, हरियाणा में वह कोई मूवमेंट के तौर पर नहीं है बल्कि सरकार का और सरकारी कर्मचारियों का उस पर इतना अधिकार है कि वह एक महकमा बना हुआ है। हर जिले में जो भी डिस्ट्रिक्ट इंस्टिट्यूट हैं, सैन्ट्रल वहा कौरी आउट करते हैं। किसी भी मुल्क में और इस मुल्क में, जहां भी यह कोआप्रेटिव का काम भुरु हुआ, वहां सबसे मोटा सिद्धान्त यह रखा गया था कि यह एक तहरीक के तौर पर होगा और वालंटरी बेसिज पर होगा। इसमें जबर्दस्ती का सवाल नहीं। इसमें ऊपर से दबाव का सवाल नहीं बल्कि लोग मर्जी से इकट्ठे होकर जो काम कर सकें वह करें और महकमे के जिम्मे जासे काम सुपुर्द हुआ था वह सिर्फ इस कदर था कि गाइडैन्स दें। पंडित जवाहर लाल नेहरू के अनुसार पंचायतस और कोआप्रेटिव ने ग्रास रूट डैमोक्रेसी के रूप में देना में काम स्पिरिट को, उस इंटैन्ट का नाबूद कर दिया गया, इसका एक महकमा बना दिया और यहां तक कि एक एक अफसर और सैक्रेटरी तक सरकार की मर्जी के खिलाफ भर्ती नहीं होते। इन सैक्रेटरीज को इंसपैक्टर्ज आदि से मिल करके आज डेढ दो करोड रूपये के गबन के केसिज लोगो के खिलाफ डाले हैं।

इस बिल मे भी कोई यह बात नही कि कोठ सुधार की बात आई हो। मेने किसी मुल्क मे दे । देखा कि कोआप्रेटर्ज की मर्जी के खिलाफ सरकार मैम्बर बना दें। यहा तो कह दिया कि जो दरखास्त दे देगा, दरखास्त देने की तारीख से वह मैम्बर बना दे। यहां तो कह दिया कि जो दरखास्त दे देगा, दरखास्त देने की तारीख से वह मैम्बर समझा जाएगा ऐसी बात हमने देखी नही। चाहे क्वालिफिके ांज पूरी करे या न करे, चाहे नाबालिग, लुनेटिक या इनसेन हो, चाहे हिस्सा दिया हो या न दया हो, चाहे डिफाल्टर हो दूसरी सोसाइटीज का, लेकिन दरखावास्त दे और मैम्बर बन जाए ऐसी बात हमने कीी सुनी नही थी न ही हमें मालूम था कि महकम इतनी हद तक जाएगा कि कमेटी चाहे या न चाहे, मैम्बर चाहे या न चाहे परन्तु दरखास्त देते ही कोई इंडिविजुअल मैम्बर बन जाएगा। सबसे चातरानाक क्लाज इसमे एक और डाली गई है जैसे वर्मा साहब ने बताया इसके अनुसार 12-13 के करीब सरकारी मैम्बर हो सकते हैं। सरकार जिसको चाहेगी उसको मैम्बर बना देगी। उदाहरण के लिए मै क्लाज 4 की सब-क्लाज (बी) पढ देता हूं। इस क्लाज के जरिए ये सैक 1 न 26 मे तरमीम करने चले है।

“(b) where the employer has contributed to the share capital of the employees co-operative society to the extent of two thousand and five hundred rupees or more, the employer shall have the right to nominate three members or one-third of the total number of members thereof, whichever is less, on the committee of such society.”

स्पीकर साहब, भूगर मिलज के केन ग्राओर्ज की सोसाइटीज है। केन ग्राओर्ज की सोसाइटीज मे ऐम्पलायर की, जो मिल ओनर्ज है ज्यादा से ज्यादा इस बात की कोर्णित है कि उन पउ वह कंट्रोल रखें। जमुनानगर के इलाके मे, कितने ही केन ग्राओर्ज न का तकारों ने अपनी सोसाइटीज बनाई है लेकिन बहुत अर्से से उनके बाई लोज मे एक क्लाज थी कि भूगर मिल जमुनानगर जो है, यानी सरस्वती भूगर मिल वह एक डायरैक्टर नामिनेट कर सकती है। उस पर डायरैक्टर न भी जो केन ग्राओर्ज थें उनके हकूक को खराब करने मे या उनको परे तान करने मे कोई कसर नहीं रखी थी। सन् 1965 मे वह जो बाईलपज मे क्लाज थी उसके बारे मे हमने कहा कि चूंकि यह ऐक्अ की मं ता के खिलाफ है इसलिए इसको डिलीट कर दिया जाए। तब जाकर के कहीं वह क्लाज उड़ाई गई। लेकिन आज सरकार क्या करती हैं उन मिल आनर्ज का पूरा दबदबा केन-ग्राओर्ज की सोसाइटीज मे लाने के लिए कह दिया कि अगर अढाई हजार रूपया वह दे दे तो तीन डायरेक्टर बना सकते हैं। ये जो एम्स एंड आबजैक्टस है इसमे इनहोने यह नहीं दिया। उसमे यह छुपा कर रखा है और बातो के बारे मे जिक्र किया है इंडस्ट्रियल कारपोरे तान और गवर्नमेंट के मैम्बरर्ज हम क्यो कर रहे है। ऐम्पलायर्ज का दे ता भर मे हमने कही नहीं देखा कि 2500 रूपया दे और तीन मैम्बर्ज बना लें। तीन सरकार के हो गए, तीन फाईनैस कारपोरे तान के हो गए, दो ऐक्सपर्ट हो गए। दूसरी ऐन्टरप्रन्योर्ज है। जो नौजवान लड़के है, अनऐम्पलाएज ग्रेजुएटस है टेकिन तायन्ज है, वे अपना

धन्धा भुरु करना चाहते है तो सरकार ने यह कर दिया कि सरकार यदि दस लाख रूपये कर्जा दे देगी तो उसमे मैनेजिंग डायरैक्टर और डारैक्टर रखेगी। डायरैक्टर का जहां तक ताल्लुक है वह तो ठीक है लेकिन मैनेजिंग डायरैक्टर की सारी पावर्ज के साथ जो भी कमेटी की पावर्ज है उनको सुपरसीड करके अगर ऐडमिनिस्ट्रैटर सरकार लगा दे तो फिर इसको क्या कहते है कि यह कोआप्रेटिव सोसाईटी का महकमा है? डिपार्टमेंट जहा चाहे सोसाईटी खुलवा सकता है। लेकिन इस तरह से यह तहरीक है, यह हरियाणा से खत्म होती जा रही है। स्पीकर साहब, तो खुद इस महकमें के इन्चार्ज रहें। आपने भी इसमे काफी रिफार्म किये है, लोगो की सहूलियते दी है। आपके टाईम पर भी इस महकमे ने काफी तरक्की की थी। कोआप्रेटिव मूवमेंट पर डिपार्टमेंट का इतना कंट्रोल नही होना चाहिए। आप बे एक सैक इन 60-ए भी लागे कर दे लेकिन इसके बावजूद भी क्या नतीजा होता जा रहा है कि लोगो मे दह गत बढती जा रही हैं कोआप्रेटिव सोसाइटी का टैरेर है। गांवो मे लोगो ने प्राईवेट मनी-लैन्डर्ज से पैसा लेना भुरु कर दिया है। फसल के मौके पर कोआप्रेटिवप डिपार्टमेंट के अफसरान जीप मे जाते है और रात को ही लोगो का पकड़ लाते है। यहा तक हालत है कि खेतों मे जाते है खेतों मे काम करते हुए लोगों को हल चलाते हुए पकड़ लाते है। खेत मे हल खड़े का खड़ा रह जाता है। इस तरह से उस गरीब का खेत बिना उपज के रह जाता है। उन गरीबो को पकड़ लाते है ओर अपने दफ्तर के कमरों मे या बाथरूम मे रोक देते है, जेल मे नही

रोकते हैं। उनके घर वाले मारे मारे फिरते हैं कि कहां गया, जेले में मिलता नहीं, घर पहुंचता नहीं है। इस तरह से घर वालों को भी परेशान किया जाता है। स्पीकर साहब, मुझे याद है कि बहुत अर्से पहले सरदार इकबाल सिंह, ज्वायंट रजिस्ट्रार होते थे। वे रोहतक और करनाल जिले में लगे हुए थे। उनको भी इसी तरह से जबरदस्ती देहातीयों से पैसा रिकवर किया था, तब भी यह कोआप्रेटिव मूवमेंट खत्म सी हो गई थी।

अब फिरप दुबारा लोगों में अन्दर प्रचार किया गया था, फिर वह चालू हुई थी। अब जो ढंग सरकार ने अपनाया है इससे यह तहरीक बिल्कूल खत्म हो जायेगी। गरीब आदमी जो कोआप्रेटिव सोसाइटीज से पैसा ले लेते थे, अब उनको फिर मनी-लैंडर्ज से पैसा लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अगर कोआप्रेटिव की यही नीति रही तो कोआप्रेटिव के नजदीक हरियाणा में कोई भी आदमी नहीं जायेगा और यह तहरीक खत्म हो जायेगी।

इन भावों के साथ स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि जहां इस "बिल" से सरमायदारों का कन्ट्रोल होगा जैसे भूगर मिल बैंक्स है या और इस किस्म की दूसरी सोसाइटीज है तो यह तहरीक बिल्कूल खत्म हो जायेगी। जो नौजवान तबका अन-एम्पलायड है, थोड़ा बहुत अपना काम करना चाहता है, वह भी नहीं करेगा। सरकार ने जितने भी सेक्रेटरी वगैरह लिए हैं, वे अपनी मर्जी के मुताबिक लिए हैं। तो यह कोई

इन्साफ की बात नहीं है। तो यह कोई इन्साफ की बात नहीं है इस तरह से हरियाणा कोआप्रेटिव को तरक्की नहीं मिलेगी बल्कि खत्म हो जायेगी।

श्री के.एन. गुलाटी(फरीदाबाद): स्पीकर साहब, यह जो बिल हमारे सामने है यह बहुत अच्छा बिल है। यह बिल बड़ी भुद्व भावना से लाया गया है। खामखाह ही क्रिटिसिजम करना कोई अच्छी बात नहीं है। सरकार जो भी बात करती है वह बड़ी सोच समझ के साथ करती है। कोआप्रेटिव सिस्टम को चालू किया गया है यह डेमोक्रेटिक, लोकतंत्रीय तरीका है। सरकार ही इस बात को भली प्रकार से जानती है कि जनता के हिज मे होगा या उसके उलट होगा। कहना तो आसान है लेकिन करना बड़ा मु् कल है। चीफ मिनिस्टर साहब या दूसरे मंत्री साहेबान दिनरात मेहनत करके योजना बनाते है, कोई आसान काम नहीं है क्रिटिसिजम करना तो आसान है। सरकार को अच्छी तरह से पता है कि यह अच्छा है या बुरा है या जो भी किया है यह बिल्कूल लोकतन्त्र तरीके से ठीक किया है।

स्पीकर साहब, मै आपके जरिए सरकार के नोटिस मे एक बात लाना चाहता हूं कि हमारे जो कोआप्रेटिव कन्जयूमर स्टोर है उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हमारे यहां फरीदाबाद मे एक लाख रूपये का सामान स्टोर मे पड़ा हुआ है।

चौधरी रिजक राम: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। इसकी क्लिबल के साथ क्या रैलेवेन्सी है? The hon. Member should speak either on any clause or on the provisions of the Bill.

Mr. Speaker: Order please.

श्री के.एन. गुलाटी(फरीदाबाद): जब ये गलत लाईन पर चलते हैं तो इसको नहीं रोका जाता

Mr. Speaker: Order please. जो इरनेलेवेन्ट होगा, उन सब को रोकना मेरा काम होगा।

श्री के.एन. गुलाटी(फरीदाबाद): मैं चाहता हूँ कि स्टोर में जो स्टॉक हुआ है उसको डिस्पोज आफ किया जायें। वहाँ पर कुछ कपड़ा भी सील किया गया है। वह वहाँ पर खराब हो रहा है। जो भी इस गलती के जिम्मेदार है उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जायें। जिसका वह कपड़ा है उसको फेसला करके दे दिया जायें। इन भावों के साथ मैं इस बिल की तार्ईद करता हूँ।

चौधरी फूल चन्द (मुलाना अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, जो मौजूदा अमैन्डमेंट सदन के सामने है मैं इसकी तार्ईद करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आनरेबल मैम्बर चौधरी रिजक राम जी ने इस बिल के बारे में काफी क्रिटिसिज्म किया है और कोआप्रेटिव डिपार्टमेंट के बारे में यह भी कहा कि यह हिन्दूस्तान में काफी बदनाम हो गया है। मैं बड़े अदब के साथ चाहूँगा कि

कुछ वैस्टिड इन्डस्ट्रीज जो थे इस कोआपरेटिव महकमें मे छाए हुए थें और गरीब तबके तक इसका हवा का झोंका तय नही जाने देते थें। उन लोगों के इन सोसाइटीज पर छा जाने की वजह से गरीब लोगो के अगूंठे लगवा कर पैसा ले लेतू थे और बाद मे वे गरीब बेचारे खिंचें खिंचे फिरते थे। इस प्रकार की सब गड़बड़ी को बन्द करने के लिए और लोगो की भलाई के लिए सरकार कुछ अमेंडमेंट करना चाहती है लेकिन ये अपोजी इन के भाई उन गरीबों की भलाई नही देखना चाहते है। इसके पेट मे दर्द होता हैं। तो मै समझता हूं कि इस बिल मे जो भी अमेंडमेंट सरकार लायी है वह बहुत प्रोग्रेसिव है, वीकर सैव इन की भलाई के लिए है और वीकर सैव इन का मनैजमेंट मे हाथ हो, सोसाइटी मे हाथ हो, उसके लिए लायी हैं जो कुछ भी किया गया है हालात के मुताबिक, संसार के हालात को देखते हुए वीकर सैव इन को ऊंचा उठाने के लिए ये अमेंडमेंट लायी गई है।

श्री गिरी । चन्द्र जो ि (यमुनानगर): स्पीकर साहब, मै ज्यादा नही कहना चाहता हूं। मुझे तो हंसी इस बात पर आती है कि चौधरी रिजक राम जो इतने सीजन्ड पोलीटि ियन है इन्होने इस बिल के अनैक्सचर को नही पढां। अगर उन्होने इसके अनैक् िचर को पढा होता तो यह देख लिया होता। उसमे लिखा है:—

“Provided further where the employer has contributed to the share capital of teh employee Co-Operative Societies to the extent of Ruppes 2500 or more the employer

shall have right to nominate three members or one-third of the total members, whichever is less, on the committee of such society.”

वही चीज इस बिल में रखी गई है। अगर उसके एम्ज आब्जैक्ट्स को पढ़ा जाता तो उनका सही पता लग जाता। इस बिल में अमेंडमेंट लाने का मकसद ही यह है कि वीकर सैव इन का आज तक सोसाईटीज की कोऑपरेटिव मूवमेंट में कोई मौका ही नहीं मिला और उन्होंने गरीब लोगों को दबाया हुआ था आज इस चीज को दूर करने के लिए मौका मिला है कुछ इम्प्रूवमेंट की है। इन भावों के साथ मैं इस बिल की ताइद करता हूँ।

12.00 बजे

गृह मंत्री स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्रीमती भारदा रानी):
माननीय अध्यक्ष महोदय यह जो कोऑपरेटिव का बिल अभी आया है और इसमें चौधरी शिव राम वमरा जी ने कुछ भावों के साथ इसका क्रिटिसिज्म शुरू किया। पहली बात तो यह कही कि यह जो क्लॉज 2 है इसका कोई ऐक्सट्रैक्ट ही नहीं दिया गया है। इस विषय में ऐक्सट्रैक्ट की ऐसी बात नहीं थी। इसमें यह सिर्फ डेफिनेशन को रिलेट करता है कुछ नई डेफिनेशन जो यहां पर दे दी गई है जैसे वीकर सैव इन के बारे में है कि वीकर सैव इन मीन्स:—

(i) Agriculture labourers, marginal farmers and small farmers, as defined in section 2 of the Haryana Relief of Agriculture Indebtedness Act, 1976;

(ii) members of Scheduled Castes and such other economically and socially backward or neglected persons as the Government may, from time to time, specify in this behalf”.

तो इस तरह से अध्यक्ष महोदय, इस एक्ट में जो अमेंडमेंट की जा रही वह सोसाइटी में, साज में जो एक वाछिंत चीज है समे एक बड़ी भारी ड्रास्टिक चेंज लाने के लिए यह अमेंडमेंट की गई है। अब तक ये जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी उनके अन्दर एक बड़ी अजीब स्थिति थी। इसमें ऐसा पदाधिकारी ही नहीं थे जो उसका डीक से संचालन कर सकें। कोऑपरेटिव सोसाइटीज या उसके कागजात या उसके रजिस्टर किसी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए सैक्रेटरी होता था। इस तरह की बहुत सारी सोसाइटीज थी और आपने देखा होगा अध्यक्ष महोदय आपके पास भी यह डिपार्टमेंट काफी समय तक रह चुका है कि कितनी भारी संख्या में इस प्रकार की दखास्ते आती थी कि पैसा किसी ने लिया और नाम किसी के चढ़ रहा है। जब सोसाइटी के पदाधिकारी कर्मचारी वसूल करने के लिए जाते थे तो जिसने वह पैसा नहीं ले रखा है वे उन गरीब आदमियों से डिमाण्ड करते थे और फिर इंकवायरी, वसूली की बड़ी भारी परे गानियों का सामना लोगो का करना पड़ता था। आज भी उन पुरानी सोसायटियों की दखास्ते बराबर हमारे पास इन्हीं भाईयों

के जरिए आती है और बहुत सारी िकारयेत आती है। इनप कमियों को दूर करने के लिए हमने सारी सोसायटिदयो को अमलगामेट करके एक बहुत अच्छ बाचबल यूनिट में परिवर्तित कर दिया है। 14 हजार सोसायटीज में से 2138 सोसायटीज हमने हरियाणा के अन्दर बना दी हैं एक पटवार सर्किल में एक सोसाईटी बनाई है तो एक बड़ा बाचबल यूनिट होगा जिसके अन्दर एक होल टाईम मैनेजर होगा और साथ ही उसकी एक्सीविटीज पर अच्छी नजर रहेगी। चैक के जरिए पैसा दिया जाएगा और जो गड़बड़ी अब तक होती रही है उसको पूरी तरह से चैक किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, उसके लिए उसमें एक नई जो तरमीम की गई है वह यह है कि जब तक जो सोसायटीज लोन देतरी थी उसमें आम तौर पर ऐग्रीकलचार लोन ही दिए जाते थे लेकिन देहात के अन्दर जो दूसरे लोग हैं हरिजन हैं िडयूल्ड कास्टस हैं बैकवर्ड हैं आटिजंज हैं उनको अब तक कोई लोन इन सोसायटीज के द्वारा नहीं दिया जाता था। क्योंकि आज समाज में हमारी प्रधान मंत्री के आदेशानुसार एक बहुत बड़ी क्रांति चल रही हैं इन लोगों को भी दूसरे लोगों के साथ मिलाकर चलना है तो इसलिए उनको भी अब लोन देने का प्रोवीजन किया गया है। उनको जब लोन देने का प्रोवीजन किया गया है तो स्वाभाविक बात है कि इन लोगों को सोसायटीज का मैम्बर बनाना जरूरी हैं और मैम्बर्ज होना जरूरी है तो यह भी जरूरी है कि इनका रिप्रिजैन्टे िन भी इन कमेटीज के अन्दर होना चाहिए। वन थर्ड रिप्रिजेन्टेटिव इनके इन कमेटीज में रखे जाएंगे और इस चीज का

तो इन भाईयों को बड़ा हर्ष होना चाहिए। वन थर्ड रिप्रिजेन्टेटिव इनके इन कमेटीज में रखें जाएंगे और इस चीज का तो इन भाईयों के बड़ा हर्ष होना चाहिए इनको बड़ा स्वागत करना चाहिए कि ऐसे तबके की तरफ सोसायटी देख रही है जिनकी तरफ पहले कभी नहीं देखा गया था तो यह एक बड़ी अच्छी बात है। क्रिटिसिजम करना एक अलग बात है। दूसरी बात, चौधरी रिजक राम ने कहा कि जबरदस्ती मैम्बर बनाया जा रहा है। जबरदस्ती मैम्बर कहा बनाया जाता है? क्या कोई जबरदस्ती ऐप्लीकेशन देगा? ऐप्लीकेशन देने का मतलब है कि उस आदमी ने इच्छा जाहिर की कि वह सोसायटी का मैम्बर बनना चाहता है उस आदमी ने इच्छा जाहिर की कि वह सोसायटी का मैम्बर बनना चाहता है और दूसरी जो कंडीशन है वे जरूर पूरी की जाएगी। वे पूरी करने के बाद उस आदमी को उस दिन से मैम्बर माना जाएगा जिस दिन ऐप्लीकेशन देता है। इसका मतलब यह है कि जिस दिन उसने ऐप्लीकेशन दी उस दिन से उसने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है वह सोसायटी का मैम्बर होना चाहता है। इच्छा जाहिर करने का मतलब जबरदस्ती तो होता नहीं है पता नहीं कि उन्होंने कैसे यह भाव कह दिए कि जबरदस्ती मैम्बर बनाया जा रहा है।

एक दूसरी बात उन्होंने और कही कि ऐम्पलाइज्ड यहाँ ऐम्पलाइज्ड की कोऑपरेटिव सोसायटी में 2500 रुपये देगे तो वहाँ तीन मैम्बर अपने नौमिनैट कर सकते हैं और उनका उन्होंने

क्रिटिसीज्म किया और उसमे उन्होंने अध्यक्ष महोदय, भूगकेन ग्रीअर्ज की जो सोसाइटीज है उनका उदाहरण दिया। जो भूगरकेन ग्रीअर्ज है they are not the emplyees of anybody, invidividual or sugar-cane grower's society. वह तो अपनी इंडिपेन्डेंट कोआप्रेटिव सोसायटीज की जद मे नही आती है। एम्पलाईज कोआप्रेटिव सोसायटीज की जद मे वह सोसायटीज की जद नही आती है। एम्पलाईज कोआप्रेटिव सोसायटी की जद मे वह सोसायटी आती है जहां कोई मिल के या दूसरी किसी संस्था क ऐप्लायज हो वे अपनी सोसायती बनाए और उसमे उनका एम्पलायर अपना 25 सौ रूपया डाले या उससे ज्यादा डाले तो वह अपने तीन मैम्बर या वन थर्ड जो भी नम्बर कम हो उतने मैम्बर उसको उसमे नौमिनेट करने का अधिकार होगा। इस पर भी उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने पूरा उन पर कन्ट्रोल कर लिया है फिर काहे की इंडिपैन्डेंस रही। अध्यक्ष महोदय, आपको पता होगा कि किसी भी सोसायती या बैंक्स या दूसरी जो कोआप्रेटिव बोडीज है वहा पर गवर्नमेंट के पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा दिया जाता है अदरवाईज वह काम नही कर सकती ओर कही-कही पर सरकार ने बहुत बड़ी रकम ही उसके लिए ग्रान्ट भी दी हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि सोसायटीज की हालत क्या रही हैं वैस्टिड इन्ट्रैस्टस ने सारे पैसे को खा लिया, खत्म कर दिया या मिसयूज कर दिया और चीज घाटे मे गई। तो अगर सरकार का रिप्रेजेन्टे इन या उन बोडीज का रिप्रेजेन्टे इन उन कमेटीज मे नही रहेगा तो जो फाईनैन्स करे जो उनका भोयर मनी

है वह तो गया ही और हाथ में जो सरकार ने ग्रांट दी है, सरकार ने जो पैसा दिया गि फाईनैन्स एंड कार्पोरेट्स ने जो पैसा दिया, उनका पैसा भी साथ में गया। उनके इंस्ट्रुमेंट्स को सेफगार्ड करने के लिए और वाच करने के लिए कि कहीं पैसों का मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं। वह वैस्टिड इंस्ट्रुमेंट्स उनका रिप्रिजेंटेशन होना बहुत जरूरी है लेकिन मैजोरिटी जो होगी वहां पर उन रिप्रिजेंटेटिव्स की ही रहेगी जो कोर्पोरेटिव्स के रिप्रिजेंटिव हैं या लोगों के रिप्रिजेंटेटिव्स हैं उनकी मैजोरिटी रहेगी और वहां पर कोई इस प्रकार की बात नहीं होगी जिससे यह कहा जा सके कि उनके ऊपर कोई जबरदस्ती की जा रही है। इन सब बातों से और दूसरी चीजों से ये चेजिज हुई है। अध्यक्ष महोदय, अगर वे स्टैटमेंट आफ आबजैक्ट्स एंड रीजन्स पढ़ते तो साफ हो जाता कि पहली चीज तो सबसे बड़ी यह कि जो वीकर सर्विस है उसको रिप्रिजेंटेशन देने के लिए की गई है दूसरे उन्होंने कहा कि यह जो सोसायटीज के 25 सौ रूपए वाली बात कही है कि गवर्नमेंट वहां पर अपना कोई नोमिनी रखेगी, यह ऐक्ट में प्रोवाइडिड है, यह कोई नई अमेंडमेंट नहीं है तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष महोदय, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि जरा ऐक्ट को अच्छी तरह से पढ़ें और जो अमेंडमेंट आई है उसको भी अच्छी तरह से पढ़ें और वह ऐप्रिप्रियेट करेगा कि इस समय कोर्पोरेटिव डिपार्टमेंट के अन्दर या इसकी वर्किंग के अन्दर ड्रास्टिक चेंज लाई जा रही है ताकि ज्यादा अच्छी तरह से यह

डिपार्टमेंट काम करें, ज्यादा सफल हो सके। इन भाब्डों के साथ मे मै निवेदन करूंगी कि इस बिल को पास कर दिया जाए।

Mr. Speaker: Question is—

That this house disapproves the Punjab Co-Operative Societies (Haryana Second Amendment) Ordinance, 1976 (Haryana Ordinance No.2 of 1976)

The Motion was carried.

Mr. Speaker: Question is—

That this house disapproves the Punjab Co-Operative Societies (Haryana Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The Motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will take up the bill clause by clause.

Clauses 2 & 8

Mr. Speaker: Question is—

That Clauses 2 and 8 stand part of the Bill.

The Motion was carried.

Clauses 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clauses 1 stand part of the Bill.

The Motion was carried

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The Motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the title of the Bill.

The Motion was carried.

State Minister for Home and Health (Shrimati Sharda Rani): Sir, I beg to move—

That the Punjab Co-Operative Societies (Haryana Second Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion Moved—

That the Punjab Co-Operative Societies (Haryana Second Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Punjab Co-Operative Societies (Haryana Second Amendment) Bill be passed.

The Motion was carried

दि ईस्ट पंजाब मोलैसिज (कन्ट्रोल) हरियाणा अमैटमैट बिल, 1976

Excise and Taxtion Minister (Shri Shyam Chand):

Sir, I beg to introduce the East Punjab Molasses (Control) Haryana Amendment Bill, 1976.

Sir, I beg to move—

That the East Punjab Molasses (Control) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion Moved—

That the East Punjab Molasses (Control) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is—

That the East Punjab Molasses (Control) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

The Motion was carried

Mr. Speaker: Now the House will take up the bill clause by clause.

Clauses 2

Mr. Speaker: Question is—

That Clauses 2 stand part of the Bill.

The Motion was carried.

Clauses 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clauses 1 stand part of the Bill.

The Motion was carried

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The Motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the title of the Bill.

The Motion was carried.

Excise and Taxtion Minister (Shri Shyam Chand):

Sir, I beg to move—

That the East Punjab Molasses (Control) Haryana Amendment Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion Moved—

That the East Punjab Molasses (Control) Haryana Amendment Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the East Punjab Molasses (Control) Haryana Amendment Bill be passed

The Motion was carried

दि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूटस (हरियाणा अमैडमैट) बिल, 1976

Transport Minister (Shri K.L. Poswal): Sir, I beg to introduce the Industrial Disputes (Haryana Amendment) Bill, 1976.

Sir, I beg to move—

That the Industrial Disputes (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion Moved—

That the Industrial Disputes (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once

Mr. Speaker: Question is—

That the Industrial Disputes (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once

The Motion was carried

Mr. Speaker: Now the House will take up the bill clause by clause.

Clauses 2

Sh. Gulab Singh Jain (Hissar): Sir, I beg to move—

In parts (ii) for the words “or an Administrative Secretary to Government”, the words or an Administrative Secretary to Government or and officer of the Labour

department not below the rank of a Joint Labour Commissioner” be substituted.

Mr. Speaker: Motion Moved—

In parts (ii) for the words “or an Administrative Secretary to Government”, the words or an Administrative Secretary to Government or and officer of the Labour department not below the rank of a Joint Labour Commissioner” be substituted.

Mr. Speaker: Question is—

In parts (ii) for the words “or an Administrative Secretary to Government”, the words or an Administrative Secretary to Government or and officer of the Labour department not below the rank of a Joint Labour Commissioner” be substituted.

The Motion was carried

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 2 as amended, Stand part of the bill.

The Motion was carried

Sh. Gulab Singh Jain(Hissar): Sir, I beg to move—

In parts (ii) for the words “or an Administrative Secretary to Government”, the words or an Administrative Secretary to Government or and officer of the Labour department not below the rank of a Joint Labour Commissioner” be substituted.

Mr. Speaker: Motion Moved—

In parts (ii) for the words “or an Administrative Secretary to Government”, the words or an Administrative Secretary to Government or and officer of the Labour department not below the rank of a Joint Labour Commissioner” be substituted.

Mr. Speaker: Question is—

In parts (ii) for the words “or an Administrative Secretary to Government”, the words or an Administrative Secretary to Government or and officer of the Labour department not below the rank of a Joint Labour Commissioner” be substituted.

The Motion was carried

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 3, as amended, Stand part of the Bill.

Clauses 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clauses 1 stand part of the Bill.

The Motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The Motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the title of the Bill.

The Motion was carried.

Transport Minister (Shri K.L. Poswal): Sir, I beg to move—

That the Industrial Disputes (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion Moved—

That the Industrial Disputes (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Industrial Disputes (Haryana Amendment) Bill be passed.

The Motion was carried

दि पंजाब खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड (हरियाणा अमैडमैट)
बिल, 1976

Industries Minister (Shri Harpal Singh): Sir, I beg to introduce the Punjab Khadi and Village Industries Board (Haryana Amendment) Bill, 1976.

Sir, I beg to move—

That Punjab Khadi and Village Industries Board (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion Moved—

That Punjab Khadi and Village Industries Board (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is—

That Punjab Khadi and Village Industries Board (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The Motion was carried

Mr. Speaker: Now the House will take up the bill clause by clause.

Clauses 2 and 3

Mr. Speaker: Question is—

That Clauses 2 and 3 stand part of the Bill.

The Motion was carried.

Clauses 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clauses 1 stand part of the Bill.

The Motion was carried

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The Motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the title of the Bill.

The Motion was carried.

Industries Minister (Shri Harpal Singh): Sir, I beg to move—

That Punjab Khadi and Village Industries Board (Haryana Amendment) Bill passed.

Mr. Speaker: Motion Moved—

That Punjab Khadi and Village Industries Board (Haryana Amendment) Bill passed.

Mr. Speaker: Question is—

That Punjab Khadi and Village Industries Board (Haryana Amendment) Bill passed.

The Motion was carried

दि हरियाणा रेज-कोर्सिज लाईसैंसिंग बिल, 1976

Excise and Taxation Minister (Sh. Shyam Chand):
Sir, I beg to introduce the Haryana Race-Courses Licensing Bill, 1976.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Race-Courses Licensing Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion Moved—

That the Haryana Race-Courses Licensing Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is

That the Haryana Race-Courses Licensing Bill, be taken into consideration at once.

The Motion was carried.

Mr. Speaker: Now the house will take up the bill Clause by Clause.

Sub-Clauses (2) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Sub-Clauses (2) of Clause 1 stand part of the Bill.

The Motion was carried.

Clauses 2 to 12

Mr. Speaker: Question is—

That Clauses 2 to stand part of the Bill.

The Motion was carried.

Sub-Clauses (1) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Sub-Clauses (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The Motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The Motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the title of the Bill.

The Motion was carried.

Excise and Taxation Minister (Sh. Shyam Chand):

Sir, I beg to move—

That the Haryana Race-Courses Licensing Bill passed.

Mr. Speaker: Motion Moved—

That the Haryana Race-Courses Licensing Bill passed.

Mr. Speaker: Question is

That the Haryana Race-Courses Licensing Bill passed.

The Motion was carried.

दि पंजाब भूदान यजना (हरियाणा अमैडमेंट) बिल,
1976

Revenue Minister (Pandit Chira): Sir, I beg to introduce the the Punjab Bhudan Yagna (Haryana Amendment) Bill, 1976.

Sir, I also beg to move—

That the Punjab Bhudan Yagna (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion Moved—

That the Punjab Bhudan Yagna (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is

That the Punjab Bhudan Yagna (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The Motion was carried.

Mr. Speaker: Now the house will take up the bill Clause by Clause.

Clauses 2 to 5

Mr. Speaker: Question is—

That Clauses 2 to 5 stand part of the Bill.

The Motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The Motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The Motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the title of the Bill.

The Motion was carried.

Revenue Minister (Pandit Chira): Sir, I beg to move—

That the Punjab Bhudan Yagna (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion Moved—

That the Punjab Bhudan Yagna (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is

That the Punjab Bhudan Yagna (Haryana Amendment) Bill be passed.

The Motion was carried.

दि डौरी प्रोहिबि ान (हरियाणा अमैडमैट) बिल, 1976

Excise and Taxation Minister (Sh. Shyam Chand):

Sir, I beg to introduce the Dowry Prohibition (Haryana Amendment) Bill, 1976.

Sir, I also beg to move—

That the Dowry Prohibition (Haryana Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion Moved—

That the Dowry Prohibition (Haryana Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is

That the Dowry Prohibition (Haryana Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

The Motion was carried.

चौधरी ि ाव राम वर्मा (नीलोखेंडी): अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में दो तीन सुझाव देना चाहता हूँ क्योंकि इसमें काफी

डिसक्रिमिने ान की गई हैं। पहले इसके आब्जैक्ट एंड रीजंज मे जो दिया गया है उसके बारे मे मै कहूंगा कि इसमें कहा गया है कि पति को कम्पैल किया जाए कि वह पत्नी का खर्चा ओटे। तो इसमे केवल पति को ही पत्नी का खर्चा ओटने के लिए कम्पैल किया जाएगा, यदि पति को पत्नी को छोड़ कर चली जाए तो वह क्या वह भी उसको खर्चा देगी। हमने कई जगह देखा है कि पत्नी पति को छोड़ कर चली जाती है तो वह बेचारा मारा मारा फिरता रहता है. . . .

विकास एवं स्त्रीनीय प्र ासन राज्य मंत्री(चौधरी गोवर्धन दास चौहान): क्या आपको तो कोई खतरा नहीं हो गया? (हंसी)

चौधरी ि ाव राम वर्मा : केवल मेरे को नहीं, आपको भी खतरा हो सकता है।

श्री अध्यक्ष: : इनके तो पहले ही 12 बच्चे है इनको क्या खतरा हो सकता है। (हंसी)

चौधरी ि ाव राम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, कई बार ऐसा होता है कि लड़के वालो को लड़की वालो को पैसा देना पड़ता है तो अगर पत्नी बाद मे उसे छोड़ कर चली जाए तो उसके पैसे बेकार जाएंगे इसलिये यह भारत दोनो तरफ लगाई जाए। इसके अलावा एक डिसक्रिमिने ान मै और समझता हूं। सैक ान 2 की बी मे आया है कि:—

(b) by the parents of either party to a marriage or by any other person, or either party to the marriage or to any other person;

इससे आगे है कि:—

at or before or after the marriage as consideration for the marriage of the said parties, but

यह जो बट है यह क्यों है, इसमें सारी चीजें होनी चाहियें

but does not include dower or mahr in the case of person to whom the Muslim Personal Law (Shariat) applies.

यह नहीं होना चाहिये। जो भी कानून भलाई का समझते हों वह सब के ऊपर लागू होना चाहिये। इस तरह की डिसक्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिये। इससे आगे क्लॉज 3 की सब क्लॉज 'एफ' में लिखा है:—

“3. Bar of certain acts.& No Person shall-

* * * * *

(f) deny conjugal rights to his wife on the ground that dowry has or the dowry given is insufficient.

ट्रेजरी बैंचिज की तरफ से आवाजे: मेरे पास जो काफी है इसमें तो 'has not given' लिखा

चौधरी शिव राम वर्मा : मेरे पास जो कापी है इसमें तो 'has been given' लिखा वह आप पता नहीं कहां से ले आए है? उसके पति के ऊपर तो जिम्मेदारी डाली गई है अगर वह अपनी पत्नी को ठीक तरह नहीं रखता तो उसको उसे खर्चा बरदास्त करने का प्रोवीजन आपने इसमें नहीं रखा जो कि होना चाहिए, मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि हमारे गांव के आसपास ढहे कौम (डैड्यूल्ड कास्ट्स) के लोग हैं उनके यहां पर रिवाज है कि अगर लड़का लड़की वालों को 850 रूपए दे दे तो लड़की उसके पास जाती है यदि वह नहीं दे पाता तो उसको लड़की के मां बाप के घर रहना पड़ता है तो ऐसे हालात में वह लड़की जिसको पैसे देकर उसको भी तो पत्नी की ओर से खर्चा मिलना चाहिए, वह भी आप की जतना है उनका भी आप को ख्याल होना चाहिए।

मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं कि वह यह है पहले आपने 5 हजार रूपए भाादी के लिए दहेज समेत रखे थे लेकिन अब तो दहेज निकाल दिया गया है कोई दहेज नहीं दे सकता लेकिन खर्चा फिर भी आपने 5 हजार ही रखा है। यह एक अनोमलस सी चीज है जिससे कि गरीब आदमियों का लाभ होने वाला नहीं है इसलिए यह खर्चा मैं समझता हूं 5 हजार से कम करके एक हजार कर दिया जावे तो बेहतर होगा। इसके अलावा एक और बात मैं कहना चाहता हूं जो 25 बारातियों के साथ बाजे

वाले ले जाने की बात थी। यह अलग अलग न रखें बल्कि आप 25 बाराती रखें और उनके बीच में ही बाजे वाले हों?

परिवहन मंत्री(श्री के.एल. पोसवाल): स्पीकर साहब, वर्मा साहब जैसे मजबूत आदमी तो गले में ढोल डाल कर भी ले जायेंगे।

श्री अध्यक्ष: : वर्मा साहब आप और पोसवाल साहब, बाजे वालों पर झगडा क्यों कर रहे हैं। (हंसी)

चौधरी शिव राम वर्मा : स्पीकर साहब, मेरा उनसे कोई झगडा नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर वे मेरे सुझावों को मान ले तो गरीब आदमियों को ज्यादा फायदा होगा नहीं तो केवल प्रचार ही रह जायेगा।

Excise and Taxation Minister (Sh. Shyam Chand):
MR. Speaker, Sir, as the House is well aware, the Haryana Dowry Prohibition bill was passed by the Vidhan Sabha in its last session. But there were certain difficulties due to which it has not been assented to by the President.

Sir, Mr. Verma has said that there is a discrimination. If there is any discrimination, it is in favour of the weaker sex. Certainly, Rs. 5000 is the maximum limit. If anybody cannot afford to spend Rs.5000 he can spend less. But for minimum there is no limit prescribed. If a man wants to spend Rs. 5 or Rs.10 or rupee 1, there is no such fear that the marriage will not be recognised by any court of law. If a man is rich he cannot display his wealth.

चौधरी शिव राम वर्मा : आप तो हिन्दी में बोल दें ।

श्री भयाम चन्द: आप तो वर्मा साहब अंग्रेजी में पढ़ रहे थे ।

चौधरी शिव राम वर्मा : मैं तो जो आपका दिया हुआ था उसी का पढ़ रहा था ।

श्री भयाम चन्द: अध्यक्ष महोदय, दो तीन बातें इसमें थी एक जो इसमें 6 महीने की इम्प्रीजनमेंट और 5 हजार फाइन रखा था उसको गवर्नमेंट आफ इंडिया के एक्ट के मुताबिक ऐसे कर दिया है दोनों सजाएं इकट्ठी भी हो सकती हैं । इसमें स्पीकर साहब, और कोई खास चीज नहीं है, इसलिए इस को पास कर दिया जायें ।

Mr. Speaker: Question is

That the Dowry Prohibition (Haryana Amendment) bill be taken into consideration at once.

The Motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will take up the bill Clause by Clause.

Clauses 2 to 4

Mr. Speaker: Question is—

That Clauses 2 to 4 stand part of the Bill.

The Motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The Motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The Motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the title of the Bill.

The Motion was carried.

Excise and Taxation Minister (Sh. Shyam Chand):

Sir, I beg to move—

That the Dowry Prohibition (Haryana Amendment) bill, be passed.

Mr. Speaker: Motion Moved—

That the Dowry Prohibition (Haryana Amendment) bill, be passed.

Mr. Speaker: Question is

That the Dowry Prohibition (Haryana Amendment) bill, be passed.

The Motion was carried.

दि हरियाणा वैटनरी काउंसिल बिल, 1976

Finance Minister (Sh. Ram Saran Chand Mittal):

Sir, I beg to intorduce the Haryana Veterinary Council bill 1976.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Veterinary Council bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion Moved—

That the Haryana Veterinary Council bill, be taken into consideration at once.

श्री जगजीत सिंह टिक्का (नारायणगढ): स्पीकर साहब, यह बिल वैसे बहुत अच्छा है लेकिन इसमे जो बात मैने नोटिस की है उसके बारे मे गवर्नमेंट का ध्यानव दिलाना चाहता हूं। इसमे इन्होने लिखा है कि—

“Person entitled to be registered. Every person Holding any of theQualifications referred to in the schedule be entitled tto have his have his name entered in the register fo veterinary practitioners”

जो भौडयूल दी है उसमे सिर्फ वही आदमी किए है जिन्होने ग्रेजुए ान की है जब कि आदकियो के ट्रीटमेंट के लिए

जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिसीनर्स हैं जो पहले दवा दारु का काम करते थे लेकिन उनके पास डिग्रीज नहीं हैं ऐसे लोगों को रजिस्टर्ड किया हुआ है। इसलिए मैं यह सुझाव दूंगा कि इसमें यह प्रोवीजन किया जाये कि जिस आदमी ने वैट्रनरी महकमे में पैक्टिस की हो यदि वह रजिस्टर्ड होना चाहे तो वह भी हो सके। इससे लोगों को ज्यादा सुविधा होगी क्योंकि जो डिग्री होल्डर डाक्टर होते हैं वे रिटायरमेंट के बाद भी गांव में नहीं जाते, गांव में सैटल नहीं होते। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि जो कम्पाउंडर या ओर इस किस्म के काम याह जिनको इस लाइन में तजर्बा हो उनको रजिस्टर्ड करने के लिए इस एक्ट में कोई अमेंडमेंट लानी चाहिए ताकि उन्हें भी कोई सहूलियत मिल सकें।

वित्त मंत्री (श्री राम सरन चन्द मित्तल): स्पीकर साहब, यह बिल उन लोगों की रजिस्ट्रेशन के लिए रखा गया है जिन्होंने वैट्रनरी सायंस में ग्रेजुएशन की हुई है और वे प्रैक्टिस करना चाहते हैं या पहले से कर रहे हैं ताकि उन प्रैक्टिसीनर्स को कंट्रोल करने के लिए कोई रिकनाइज्ड बाडी हो। जहां तक टिक्का साहब यह फरमाते हैं कि जो कम्पाउंडर बगैरा रिटायर हो गए हैं और जिनके पास सर्विस को ऐक्सपीरिएंस अच्छा हो लेकिन वे प्रैसक्राइब्ड क्वालिफिकेशन नहीं हैं उनका भी रजिस्टर किया जाए तो उसके बारे में अलग विचार किया जाएगा। इसमें यह नहीं आसकेगा। इन अल्फाज के साथ स्पीकर साहब, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस बिल को पास कर दिया जाए।

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Veterinary Council Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Now the House will take up the bill Clause by Clause.

Sub-Clauses (2) & (3) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Sub-Clauses (2) & (3) of Clause 1 stand part of the Bill.

The Motion was carried.

Clause 2 to 36

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 2 to 36 stand part of the Bill.

The Motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker: Question is—

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The Motion was carried

Sub-Clauses (1) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Sub-Clauses (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The Motion was carried

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The Motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the title of the Bill.

The Motion was carried.

Finance Minister (Sh. Ram Saran Chand Mittal):

Sir, I beg to move—

That the Haryana Veterinary Council Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion Moved—

That the Haryana Veterinary Council Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is

That the Haryana Veterinary Council Bill be passed.

The Motion was carried.

Mr. Speaker: The House stands adjourned sine die.

12.40 बजे

(The Sabha then adjourned * sine die)